



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-20062020-220044  
CG-MH-E-20062020-220044

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 210]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 2020/ज्येष्ठ 28, 1942

No. 210]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2020/JYAISHTHA 28, 1942

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 10 जून, 2020

**सं. टीएएमपी/64/2019-डीपीटी.**—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तंगहाल पीपीपी परियोजनाओं के संबंध में पोत परिवहन मंत्रालय के 11 जुलाई, 2018 के पत्र संख्या पीडी-13/1/2018-पीपीपी एकक के अनुपालन में महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा दीनदयाल पत्तन न्यास (डीपीटी) के यौक्तिकीकरण के यानी मैसर्ज अदानी कांडला बल्क टर्मिनल प्रा.लि. (एकेबीटीपीएल) द्वारा निर्माण, प्रचालन और अंतरण (बीओटी) आधार पर डीपीटी में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के अंतर्गत बीओटी प्रचालक द्वारा विकसित शुल्क बल्क टर्मिनल के दरमानों में अनुमोदित सूचकांकित भंडारण प्रभारों में घटौती के प्रस्ताव का, इस के साथ संलग्न आदेशानुसार, निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

**मामला सं.टीएएमपी/64/2019-डीपीटी**

दीनदयाल पत्तन न्यास

-----

आवेदक

गणपूर्ति

(i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii). श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

**आदेश**

(जून, 2020 के 1वें दिन पारित)

यह मामला “तंगहाल पीपीपी परियोजनाओं” के बारे में पोत परिवहन मंत्रालय के 11 जुलाई, 2018 के पत्र संख्या पीडी-13/1/2018-पीपीपी के अनुपालन में दीनदयाल पत्तन न्यास (डीपीटी) के 21 दिसंबर 2019 के यौक्तिकीकरण के यानी मैसर्ज अदानी कांडला बल्क टर्मिनल प्रा.लि. (एकेबीटीपीएल) द्वारा निर्माण, प्रचालन और अंतरण (बीओटी) आधार पर डीपीटी में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के अंतर्गत बीओटी प्रचालक द्वारा विकसित शुष्क बल्क टर्मिनल के लिए दरमानों की अधिसूचना से संबंधित 02 जनवरी, 2015 के आदेश संख्या टीएएमपी/59/2014-केपीटी के द्वारा इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित तुना के निकट ऑफ - टेकरा स्थित शुष्क बल्क टर्मिनल के सूचकांकित भंडारण प्रभारों में घटौती के प्रस्ताव से संबंधित है।

1.2. तंगहाल पीपीपी परियोजनाओं पर एमओएस के 11 जुलाई, 2018 के उक्त पत्र की प्रति डीपीटी द्वारा अपने 21 दिसंबर, 2019 के प्रस्ताव के साथ संलग्न की गई है।

2. 21 दिसंबर, 2019 के प्रस्ताव में डीपीटी द्वारा उठाये गए मुद्दे इस प्रकार हैं:

- (i). प्राधिकरण ने अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 के अनुसार तुना के निकट टेकरा स्थित शुष्क बल्क टर्मिनल के विकास की परियोजना के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क को अधिसूचित करते हुए राजपत्र संख्या 285 के द्वारा 02 नवंबर, 2010 का आदेश संख्या टीएएमपी/42/2009-केपीटी पारित किया था।
- (ii). उक्त अधिसूचित आदेश के अनुसार निशुल्क अवधि के इतर भंडारण के लिए अनुमोदित अपफ्रंट प्रशुल्क इस प्रकार है:-

(क). **आयात/निर्यात के लिए:**

(दर रु. में प्रति एमटी प्रति दिन)

वस्तु	दर 1वें से 10वें दिन तक	दर 11वें से 20वें दिन तक	दर 21वें दिन से आगे
सभी प्रकार का कार्गो	₹2.07रु.	₹ 4.14रु.	₹ 6.21रु.

- (iii). तत्पश्चात, डीपीटी ने 30 वर्ष की रियायत अवधि के लिए बीओटी आधार पर परियोजना के विकास के लिए 27 जून, 2012 को मैसर्ज अदानी कांडला बल्क टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (एकेबीटीपीएल) के साथ रियायत करार किया। ग्राही द्वारा परियोजना के निर्माण के पश्चात, परियोजना 10 फरवरी, 2015 से प्रचालन में है।
- (iv). एमओएस ने 11 जुलाई 2018 के पत्र संख्या पीडी-13/1/2018-पीपीपी के द्वारा अध्यक्ष आईपीए की अध्यक्षता में गठित समिति की (4 अप्रैल, 2018) की रिपोर्ट के साथ सभी महापत्तन न्यासों को “तंगहाल परियोजनाओं” की तंगहाली को समाप्त करने के लिए दिशानिर्देश और निदेश जारी किये।
- (v). एमओएस ने पत्र में निर्धारित ‘तंगहाल परियोजना’ के लिए पीपीपी परियोजना के वर्गीकरण के मानदंड के अनुसार, विषयक परियोजना ‘तंगहाल परियोजना के रूप में वर्गीकृत है।
- (vi). एमओएस ने 11 जुलाई 2018 के पत्र संख्या पीडी-13/1/2018-पीपीपी एकक का पैरा 6 बताता है:-

“एएसएंडएफए, एमओएस की अध्यक्षता वाली समिति की राय यह है कि ऊपर पैरा 3 में परिभाषित तंगहाल परियोजना में जहां भंडारण प्रभारों के असामान्य होने का मुद्दा उठता है, वहां पत्तन सुग्राहियों

के साथ परामर्श करके रियायत करार के "संशोधन, आशोधन अथवा परिवर्तन" निबंधनों और शर्तों के उपबंधों के अंतर्गत भंडारण प्रभारों के यौक्तिकीकरण के लिए उपयुक्त प्रस्ताव के साथ प्राधिकरण को संपर्क कर सकते हैं ताकि प्राधिकरण के दिशानिर्देशों/अधिसूचना के अनुसार एआरआर प्राप्त किया जा सके। प्राधिकरण को ऐसे प्रस्तावों का गुण-दोषों के आधार पर सुविचार करना होगा। समिति सृजित सुविधा के इष्टतम उपयोग के लिए रियायतकर्ता प्राधिकरण द्वारा भी आवधिक तौर पर स्थिति की समीक्षा करने की सिफारिश करती है।"

(vii). तदनुसार, एमओएस के निदेशों के अनुसार परियोजना की तंगहाली को दूर करने के लिए, इस परियोजना के भंडारण प्रशुल्क के यौक्तिकीकरण का प्रस्ताव है। इस परियोजना से वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 में कार्गो की वास्तविक निकासी के आधार पर और परियोजना के मूल रूप से अनुमोदित प्रशुल्क के अनुसार परियोजना के लिए भंडारण हेतु राजस्व अपेक्षा को ध्यान में रखकर निशुल्क अवधि से इतर भंडारण का प्रस्तावित प्रशुल्क निकलता है और वह इस प्रकार है:

(क). 3 वर्षों में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर भिन्न स्लैब अवधियों में कार्गो का वास्तविक भंडारण।

टेकरा के लिए प्राधिकरण के आदेश के अनुसार	रु. लाख में
अनुमोदित प्राधिकरण आदेश के अनुसार राजस्व अपेक्षा	1168.70
राजस्व अपेक्षा की राशि	116870000

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	योग	औसत
कुल शुल्क बल्क कार्गो	37,27,851.44	4456100.00	4205212.94	12389164.38	100%
निशुल्क अवधि	13,88,894.61	1350381.99	2008611.60	4747888.20	38.32%
निशुल्क अवधि के पश्चात् 1वें दिन से 10वें दिन तक	7,14,302.28	1032021.31	502241.40	2248564.99	18.15%
निशुल्क अवधि के पश्चात् 11वें से 20वें दिन तक	567432.46	779791.50	517145.10	1864369.06	15.05%
निशुल्क अवधि के पश्चात् 21वें से 30वें दिन तक	442151.38	492321.26	445842.70	1380315.33	11.14%
निशुल्क अवधि के पश्चात् 31वें दिन से 40वें दिन तक	341767.71	280367.64	256686.46	878821.80	7.09%
निशुल्क अवधि के पश्चात् 41वें दिन से 50वें दिन तक	143820.48	197825.18	191029.57	532675.23	4.30%
निशुल्क अवधि के पश्चात् 51वें दिन से 60वें दिन तक	53836.59	133618.25	88028.43	275483.27	2.22%
निशुल्क अवधि के पश्चात् 61वें दिन से	9054.52	148112.25	59323.12	216489.90	1.75%

70वें दिन तक					
निशुल्क अवधि के पश्चात् 71वें दिन से 80वें दिन तक	43084.80	22167.89	40818.15	106070.84	0.86%
निशुल्क अवधि के पश्चात् 81वें दिन से आगे।	23506.60	19492.74	95486.42	138485.76	1.12%

(ख). निशुल्क अवधि के पश्चात् कार्गो की भंडारण वार अवधि:

से संबंधित भंडारण कार्गो									योग	कल्पित
निशुल्क अवधि के पश्चात् 81वें दिन से आगे।	निशुल्क अवधि के पश्चात् 71वें दिन से 80वें दिन तक	निशुल्क अवधि के पश्चात् 61वें दिन से 70वें दिन तक	निशुल्क अवधि के पश्चात् 51वें दिन से 60वें दिन तक	निशुल्क अवधि के पश्चात् 41वें दिन से 50वें दिन तक	निशुल्क अवधि के पश्चात् 31वें दिन से 40वें दिन तक	निशुल्क अवधि के पश्चात् 21वें से 30वें दिन तक	निशुल्क अवधि के पश्चात् 11वें से 20वें दिन तक	निशुल्क अवधि के पश्चात् 1वें दिन से 10वें दिन तक	भंडारित	यथाभंडारित
1.12%	0.86%	1.75%	2.22%	4.30%	7.09%	11.14%	15.05%	9.07%	52.60%	निशुल्क अवधि के पश्चात् 1वें दिन से 10 वें दिन तक
1.12%	0.86%	1.75%	2.22%	4.30%	7.09%	11.14%	7.52%		36.00%	निशुल्क अवधि के पश्चात् 11वें से 20वें दिन तक
1.12%	0.86%	1.75%	2.22%	4.30%	7.09%	5.57%			22.91%	निशुल्क अवधि के पश्चात् 21वें से 30वें दिन तक
1.12%	0.86%	1.75%	2.22%	4.30%	3.55%				13.79%	निशुल्क अवधि के पश्चात् 31वें दिन से 40वें दिन तक
1.12%	0.86%	1.75%	2.22%	2.15%					8.09%	निशुल्क अवधि के पश्चात् 41वें दिन से 50वें दिन तक
1.12%	0.86%	1.75%	1.11%						4.83%	निशुल्क अवधि के पश्चात् 51वें दिन से 60वें दिन तक
1.12%	0.86%	0.87%							2.85%	निशुल्क अवधि के पश्चात् 61वें दिन से 70वें दिन तक
1.12%	0.43%								1.55%	निशुल्क अवधि के पश्चात् 71वें

										दिन से 80वें दिन तक
0.56%									0.56%	निशुल्क अवधि के पश्चात् 81वें दिन से आगे।

(ग). स्लैब दर परिकलन:

निशुल्क अवधि के पश्चात् 1वें दिन से 10वें दिन तक मौजूदा स्लैब दर	2.07	X
निशुल्क अवधि के पश्चात् 11वें से 20वें दिन तक मौजूदा स्लैब दर	4.14	2x
21वें दिन से आगे मौजूदा स्लैब दर	6.21	3x

(घ). संशोधित भंडारण प्रभार परिकलन:

1	शुष्क बल्क टर्मिनल के अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारण से संबंधित प्राधिकरण द्वारा 17 अगस्त, 2010 के आदेश संख्या टीएएमपी/42/2009-केपीटी द्वारा यथा अनुमोदित भंडारण से कार्यकलाप से वार्षिक राजस्व अपेक्षा	₹11,68,70,000 (₹11.68 करोड़)	-	
2	शुष्क बल्क टर्मिनल के अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारण से संबंधित प्राधिकरण द्वारा 17 अगस्त, 2010 के आदेश के अनुसार इष्टतम क्षमता।	1,41,12,000(14.11 2 मिलियन टन पी.ए.)		
3	निशुल्क अवधि के पश्चात् 1 से 10वें दिन तक भंडारित कार्गो की मात्रा	52.60%*	X	7423246
4	निशुल्क अवधि के पश्चात् 11वें दिन से 20वें दिन तक भंडारित किये जाने वाले कार्गो की मात्रा।	36.00%*	2X	14846492
5	निशुल्क अवधि के पश्चात् 21वें दिन से आगे भंडारित किये जाने वाले कार्गो की मात्रा।	54.58%*  (22.91% + 13.79% + 8.09% + 4.83% + 2.85% + 1.55% + 0.56%)*	3X	22269738
6	एक स्लैब में दिनों की संख्या			10
7	भंडारण प्रभार आकर्षित करने वाली कुल इष्टतम क्षमता			44539476
8	निशुल्क अवधि के पश्चात् 1वें से 10वें दिन तक के प्रथम स्लैब के लिए संशोधित भंडारण दर परिकलन	=(116870000/14112000)/ * (44539476/10)		0.29
9	निशुल्क अवधि के पश्चात् 11वें से 20वें दिन तक	=0.29X2		0.57
10	21वें दिन से आगे	=0.29X3		0.86

\* डीपीटी द्वारा निशुल्क अवधि के पश्चात् वर्ष 2015-16 से 2017-18 के वास्तिक निकासी प्रतिमान के आधार पर निकाला गया भंडारित कार्गो का % है जिसके लिए विस्तृत गणना डीपीटी द्वारा प्रस्ताव के अनुलग्नक-क में दी गई है।

(ङ). संशोधित परिकलन के आधार पर निर्धारित निशुल्क अवधि के पश्चात् संशोधित प्रस्तावित भंडारण प्रभार इस प्रकार होगा:

आयात/ निर्यात के लिए:

(दर रु. में प्रति एमटी प्रति दिन)

वस्तु	1वें से 10वें दिन तक दर	11वें दिन से 20वें दिन तक दर	21वें दिन से आगे दर
सभी प्रकार का कार्गो	₹0.29	₹0.57	₹0.86

(viii). संशोधित प्रस्तावित भंडारण प्रभारों के राजस्व आकलन का 2 नवंबर, 2010 के मूल अपफ्रंट प्रशुल्क आदेश में वसूल किये जाने वाले भंडारण प्रभारों के एआरआर आकलन के साथ मिलान नीचे दिया जाता है:-

विवरण	% मात्रा	मात्रा	दर प्रति टन प्रति दिन के लिए	रु. लाख में
<b>17.8.2010 के मूल आदेश में यथा आकलित कुल इष्टतम कार्गो क्षमता</b>		14112000	10	-
निशुल्क अवधि के पश्चात् 1वें दिन से 10 वें दिन तक	52.60%	7422912	0.29	215.26
निशुल्क अवधि के पश्चात् 11वें से 20वें दिन तक	36.00%	5080320	0.57	289.58
निशुल्क अवधि के पश्चात् 21वें से 30वें दिन तक	22.91%	3233059	0.86	278.04
निशुल्क अवधि के पश्चात् 31वें दिन से 40वें दिन तक	13.90%	1961568	0.86	168.70
निशुल्क अवधि के पश्चात् 41वें दिन से 50वें दिन तक	8.09%	1141661	0.86	98.18
निशुल्क अवधि के पश्चात् 51वें दिन से 60वें दिन तक	4.83%	681610	0.86	58.12
निशुल्क अवधि के पश्चात् 61वें दिन से 70वें दिन तक	2.85%	402192	0.86	34.59
निशुल्क अवधि के पश्चात् 71वें दिन से 80वें दिन तक	1.55%	218736	0.86	18.81
निशुल्क अवधि के पश्चात् 81वें दिन से 90वें दिन तक	0.56%	79027	0.86	6.80
<b>कुल राजस्व</b>				<b>1168.58</b>

[गणितीय अशुद्धि को सुधार दिया गया है।]

- (ix). डीपीटी के 31 जनवरी, 2019 के पत्र के द्वारा किये गए अनुरोध पर, मैसर्स एकेबीटीपीएल ने 01 फरवरी, 2019 के अपने पत्र के द्वारा भंडारण के प्रस्तावित संशोधित प्रशुल्क पर अपनी सहमति प्रस्तुत की।
- (x). प्रस्तावित भंडारण प्रशुल्क के लिए संशोधित परिकलन भी विस्तार से प्रस्तुत है और इस पर डीपीटी के बोर्ड ने 06 दिसंबर, 2019 को हुई अपनी बैठक में चर्चा भी की है। उक्त के आधार पर बोर्ड ने संकल्प संख्या 94 के द्वारा परियोजना के लिए भंडारण प्रभार के प्रस्तावित यौक्तिकीकरण को अनुमोदित करने का संकल्प पारित किया। 06 दिसंबर, 2019 को हुई डीपीटी के न्यासी मंडल की बैठक में निम्नलिखित मुद्दों का संकल्प किया:
- (क). एमओएस के 11 जुलाई, 2018 के पत्र में दिये गए निदेशों के अनुकूल, बोर्ड वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2018-19 के दौरान परियोजना से कार्गो की वास्तविक निकासी के आधार पर, भंडारण प्रभारों के यौक्तिकीकृत प्रशुल्क (प्राधिकरण द्वारा पहले से अनुमोदित के अनुसार एआरआर प्राप्त करने के लिए) को अनुमोदित करने का संकल्प करता है, जैसा नीचे दिया गया है:-

(रु. प्रति एमटी प्रति दर)

संदर्भ	1 से 10वें दिन दर	11वें दिन से 20वें दिन तक दर	21वें दिन से आगे दर
संशोधित प्रस्तावित प्रशुल्क	₹0.29	₹0.57	₹0.86

उक्त प्रशुल्क 01 जनवरी 2010 और संबंधित वर्ष की 1 जनवरी के बीच डब्ल्यूपीआई में परिवर्तन के 60% की मुद्रास्फीति को सूचकांकित होंगे।

- (ख). एमओएस के 11 जुलाई, 2018 के पत्र में दिये गए निदेशों के अनुकूल, प्रस्तावित यौक्तिकीकृत भंडारण प्रशुल्क के अनुमोदन के लिए प्राधिकरण से संपर्क किया जाये। यह भी कि, एकेबीटीपीएल के 01 फरवरी, 2019 के पत्र के द्वारा दी गई सहमति को भी भंडारण प्रशुल्क प्रस्ताव के साथ प्राधिकरण को भेजा जाए।
- (ग). प्रस्तावित यौक्तिकीकृत भंडारण प्रशुल्क 11 जुलाई 2018 से प्रभावी होगा।
- (घ). प्रस्तावित यौक्तिकीकृत भंडारण प्रशुल्क की समीक्षा अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् की जायेगी यानी प्रस्तावित प्रशुल्क आरंभ में एक वर्ष के लिए अथवा समीक्षा के पश्चात् संशोधित प्रशुल्क, यदि कोई होगा, संशोधित प्रशुल्क के अनुमोदन से, जो भी बाद में हो, प्रभावी होगा।
- (xi). उपरोक्त को ध्यान में रखकर और एमओएस के 11 जुलाई 2018 के निदेशों के अनुसरण में डीपीटी प्राधिकरण को निर्धारित निशुल्क अवधि के पश्चात् निम्नलिखित संशोधित प्रस्तावित भंडारण प्रशुल्क को अनुमोदित करने का अनुरोध करता है:
- (क). आयात/निर्यात:

(दर रु. में प्रति एमटी प्रति दिन)

वस्तु	1वें से 10वें दिन दर	11वें दिन से 20वें दिन तक दर	21वें दिन से आगे दर
सभी प्रकार का कार्गो	₹0.29	₹0.57	₹0.86

- (क). उक्त प्रशुल्क 01 जनवरी 2010 और संबंधित वर्ष की 1 जनवरी के बीच डब्ल्यूपीआई में परिवर्तन के 60% की मुद्रास्फीति को सूचकांकित होंगे।
- (ख). प्रस्तावित यौक्तिकीकृत भंडारण प्रशुल्क 11 जुलाई 2018 से प्रभासी होगा।
- (ग). प्रस्तावित यौक्तिकीकृत भंडारण प्रशुल्क की समीक्षा अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् की जायेगी यानी प्रस्तावित प्रशुल्क आरंभ में एक वर्ष के लिए अथवा समीक्षा के पश्चात् संशोधित प्रशुल्क, यदि कोई होगा, संशोधित प्रशुल्क के अनुमोदन से, जो भी बाद में हो, प्रभावी होगा।

3.1. चूंकि डीपीटी के 21 दिसंबर, 2019 के प्रस्ताव में कुछ अंतर पाये गए हैं, डीपीटी को हमारे 3 जनवरी, 2020 के पत्र के द्वारा कुछेक मुद्दों पर वांछित सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। प्रत्युत्तर में, डीपीटी ने 07 जनवरी, 2020 के अपने ई-मेल के द्वारा अपना उत्तर हमें भेजा। जहां तक प्रस्तावित दरमानों को 11 जुलाई 2018 से पूर्वव्यापी प्रभावी देने के संबंध में डीपीटी द्वारा 07 जनवरी, 2020 के अपने पत्र में किये गए निवेदनों के आधार पर प्रस्ताव की पावती भेजते समय, डीपीटी को हमारे 12 जनवरी, 2020 के पत्र के द्वारा उक्त मामले में और स्पष्टीकरण देने का अनुरोध किया गया था। डीपीटी ने 23 जनवरी 2020 के अपने पत्र के द्वारा उत्तर दिया।

3.2. हमारे द्वारा मांगी गई सूचना/दस्तावेज और डीपीटी द्वारा दिये गये उत्तर का सारांश को नीचे सारणीबद्ध किया जाता है:

क्र.सं.	हमारे द्वारा मांगी गई सूचना/दस्तावेज	डीपीटी का उत्तर
(i).	यह साबित करने के लिए कि एमओएस के 11 जुलाई 2018 के पत्र के पैरा 6 के साथ पठित पैरा 3 में पीपीटी परियोजनाओं को तंगहाल परियोजना के रूप में वर्गीकृत करने के लिए निर्धारित 3 प्रतिमानों को कथित परियोजना पूरा करती है से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य।	यह साबित करने वाले दस्तावेजी साक्ष्य कि एमओएस के 11 जुलाई 2018 के पत्र में पीपीटी परियोजनाओं को तंगहाल परियोजना के रूप में वर्गीकृत करने के लिए निर्धारित 3 प्रतिमानों को कथित परियोजना पूरा करती है, से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत है जिन पर आगामी पैराओं में चर्चा की गई है। [डीपीटी की 6 दिसंबर 2019 को हुई बोर्ड बैठक की कार्य सूची मद संख्या 29, पृष्ठ संख्या 597-604 का संदर्भ लें।]
(ii).	उक्त ब्यौरा किसी व्यवसायरत चार्टरित लेखाकार के प्रमाणपत्र द्वारा सिद्ध करें जो यह प्रमाणित करे कि कथित परियोजना के वर्गीकरण के बारे में एमओएस के पत्र के पैरा 3(ii) और (iii) के अनुसार डीपीटी द्वारा तंगहाल परियोजना के रूप में घोषित करने को सिद्ध करते हैं। यह डीपीटी जैसे अन्य महापत्तन न्यासों द्वारा अपनायी गई पद्धति के अनुरूप हैं जिसने एमओएस के 11 जुलाई 2018 के पत्र के अनुसरण में प्रस्ताव दायर किया था।	एमओएस के 11 जुलाई, 2018 के पत्र के पैरा 3(ख) और 3(ग) के अनुसार रोकड़ हानि, निवल हानि और नेट-वर्थ के ब्यौरे को प्रमाणित करने के चार्टरित लेखाकार द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत है जिन पर आगामी पैराओं में चर्चा की गई है। [डीपीटी की 6 दिसंबर 2019 को हुई बोर्ड बैठक की कार्य सूची मद संख्या 29, पृष्ठ संख्या 602-604 का संदर्भ लें।]



(iii).	<p>उक्त पीपीपी परियोजना को एमओएस के 11 जुलाई, 2018 के पत्र में निर्धारित 3 प्रतिमानों के आधार पर तंगहाल परियोजना के रूप में वर्गीकृत करने के डीपीटी के न्यासी मंडल का अनुमोदन।</p>	<p>डीपीटी के 23 दिसंबर, 2019 के पत्र के साथ संलग्न 06 दिसंबर, 2019 की बोर्ड बैठक के संकल्प संख्या 94 में यह निवेदन किया गया है कि परियोजना के भंडारण प्रशुल्क के प्रस्तावित यौक्तिकीकरण को डीपीटी के बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त है। बोर्ड का उक्त प्रस्ताव कार्यसूची मद संख्या 29 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है (प्रति संलग्न)। कार्यसूची मद के अंतर्गत ऊपर क्रमांक 1 और 2 में की गई टिप्पणियों के अनुरूप विनिर्दिष्ट दस्तावेजों को प्रस्तुत करके और पीपीपी परियोजनाओं के लिए डीपीटी के कारबार सलाहकार द्वारा ऐसे दस्तावेजों का विस्तृत परीक्षण प्रस्तुत करके [डीपीटी द्वारा अपने बोर्ड की कार्यसूची मद संख्या 29, पृष्ठ संख्या 605-607] यह डीपीटी के न्यासी मंडल को प्रस्तुत किया गया कि विषयक परियोजना एमओएस के 11 जुलाई, 2018 में विनिर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार प्रतिमान(नों) को पूरा करती है, अतः विषयक परियोजना को “तंगहाल परियोजना” के रूप में वर्गीकृत किया गया है। [डीपीटी द्वारा अपने बोर्ड की कार्यसूची मद संख्या 29, पृष्ठ संख्या 552 पैरा 19.1]।</p> <p>उक्त पर सुविचार करते हुए, डीपीटी के न्यासी मंडल ने भंडारण प्रशुल्क के यौक्तिकीकरण के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इसके द्वारा यह अनुमान लगाया गया कि डीपीटी के न्यासी मंडल ने एमओएस के 11 जुलाई 2018 के पत्र में निर्धारित 3 प्रतिमानों के आधार पर विषयक पीपीपी परियोजना को “तंगहाल परियोजना” के रूप में वर्गीकरण का भी अनुमोदन कर दिया है।</p>
(iv).	<p>(क). 21 दिसंबर, 2019 के डीपीटी के प्रस्ताव के अंतिम पैरा में यह बताया गया है कि प्रस्तावित भंडारण प्रशुल्क का यौक्तिकीकरण 11 जुलाई, 2018 से प्रभावी होगा यानी डीपीटी 11 जुलाई 2018 से पूर्व व्यापी प्रभाव से संशोधन चाहता है। यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि एमओएस के 11 जुलाई 2018 के पत्र में कहीं यह नहीं कहा गया है कि तंगहाल पीपीपी परियोजना के भंडारण प्रभारों का यौक्तिकीकरण पूर्वव्यापी प्रभाव से होगा। डीपीटी अपने प्रस्ताव को उत्तरव्यापी प्रभाव से लागू करने के बारे में प्रस्ताव में उपयुक्त संशोधन करें।</p>	<p>परियोजना के भंडारण प्रभारों के यौक्तिकीकरण का प्रस्ताव 11 जुलाई, 2018 से प्रभावी होगा क्योंकि उस तारीख को एमओएस ने “तंगहाल परियोजना” के लिए दिशानिर्देश/निदेश जारी किये थे यानी तंगहाल पीपीपी परियोजनाओं के भंडारण प्रभारों के यौक्तिकीकरण सहित तंगहाली दूर करना। अतः भंडारण प्रशुल्क के यौक्तिकीकरण के डीपीटी के विषयक प्रस्ताव को प्रभावकारिता के प्रयोजन से पूर्वव्यापी प्रभाव के रूप में न समझा जाए।</p> <p>तदनुसार, डीपीटी बोर्ड द्वारा यथानुमोदित भंडारण प्रशुल्क का प्रस्तावित यौक्तिकीकरण वह तारीख जिस दिन एमओएस ने तंगहाल परियोजना के लिए दिशानिर्देश जारी किये थे। अनुमोदित समझा जाये।</p>
	<p>(ख). उक्त निवेदन के संदर्भ में, डीपीटी को यह अनुरोध किया जाता है कि वह एमओएस के 11 जुलाई 2018 के पत्र के उस संबंधित पैरा का संदर्भ</p>	<p>डीपीटी ने 22 जनवरी, 2020 के अपने पत्र के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि सामान्यतः जारी करने वाले प्राधिकारी के निदेश ऐसे निदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी होते हैं जब तक कि तारीख के प्रभाव के बारे में</p>

<p>बताएं जिसमें यह निर्धारित है कि तंगहाल पीपीपी परियोजनाओं के भंडारण प्रशुल्क के यौक्तिकीकरण के लिए महापत्तन न्यासों के प्रस्ताव 11 जुलाई, 2018 से प्रभावी होंगे। [यानी पूर्व प्रभाव से क्योंकि डीपीटी ने अपना प्रस्ताव जनवरी 2020 को दायर किया है।]</p>	<p>स्वतः निर्देशों में अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।</p> <p>इस मामले में, एमओएस का 11 जुलाई, 2018 का पत्र निर्देशों की प्रभावकारिता की विशिष्ट तारीख के लिए मौन है, परियोजना के भंडारण प्रशुल्क के यौक्तिकीकरण के वर्तमान प्रस्ताव को 11 जुलाई, 2018 से, वह तारीख जिसको एमओएस द्वारा तंगहाल परियोजना के लिए दिशानिर्देश/ निदेश जारी किये गए थे, प्रभावी किया जाएगा। अतः डीपीटी के भंडारण प्रशुल्क के यौक्तिकीकरण के विषयक प्रस्ताव को इसकी प्रभावकारिता के संदर्भ में पूर्वव्यापी प्रभाव से न समझा जाये।</p> <p>तदनुसार, डीपीटी बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित भंडारण प्रशुल्क के यौक्तिकीकरण का प्रस्ताव 11 जुलाई, 2018 से अनुमोदित किया गया है, वह तारीख जिस दिन एमओएस ने तंगहाल परियोजना के लिए दिशानिर्देश/निदेश संसूचित किये।</p>
---	--

4.1. डीपीटी ने तंगहाल पीपीपी परियोजना के बारे में एमओएस के 11 जुलाई, 2018 के पत्र संख्य पीडी-13/1/2018-पीपीपी एकक के साथ तंगहाल पीपीपी परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों पर अध्यक्ष आईपीए की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है।

4.2. एमओएस के उक्त पत्र का पैरा 3 बताता है कि एमओएस ने पत्तन संबंधी मुद्दों पर जैसे तंगहाल पीपीपी परियोजना और प्रबंधन, अनुमतियां, पत्तन प्रभारों संबंधी अन्य मुद्दों पीपीपी प्रयोक्ताओं के भंडारण प्रभार आदि के संबंध में समय पर निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष आईपीए की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। उक्त समिति ने विभिन्न महापत्तनों की पीपीपी परियोजनाओं में भंडारण प्रभारों की समस्याओं सहित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से परीक्षण करने के पश्चात् एमओएस को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उक्त समिति ने पीपीपी परियोजना को **“तंगहाल परियोजना”** के रूप में वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित प्रतिमानों की सिफारिश की।

- (क). पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान प्रहस्तित वास्तविक कार्गो से पता चलता है कि परियोजना का इष्टतम उपयोग बोली दस्तावेज के एक भाग के रूप में डीपीआर/व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार किये गए प्रक्षेपण से 70% से भी कम हुआ है;
- (ख). परियोजना एसपीवी पिछले दो वित्तीय वर्षों से लगातार नकद हानि वहन कर रही है; और
- (ग). प्रचालन अवधि के दौरान ग्राही द्वारा वहन की गई हानियों से उसके पीक नेट-वर्थ में 50% का कट लगा है।

4.3. तत्पश्चात्, एमओएस ने आईपीए की रिपोर्ट के परीक्षण और भावी कार्रवाई का मार्ग सुझाने के लिये एसएंडएफए एमओएस की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसमें जे.एस (पी) डीपीटी, वीपीटी और ओपीटी के अध्यक्ष सदस्य के रूप में थे।

4.4. सभी महापत्तन न्यासों को संबंधित एमओएस के 11 जुलाई, 2018 के पत्र का पैरा 6 बताता है कि जब कभी तंगहाल परियोजनाओं में अपसामान्य भंडारण प्रभारों का मुद्दा उजागर होता है, एमओएस के पत्र द्वारा यथा परिभाषित, पत्तन एम उपयुक्त प्रस्ताव के साथ रियायत करार के निबंधनों और शर्तों के “करार, आशोधन अथवा परिवर्तनों” के

उपबंधों के अंतर्गत भंडारण प्रभारों के यौक्तिकीकरण के लिए प्राधिकरण को संपर्क करेगा ताकि वह ग्राही के साथ परामर्श से प्राधिकरण दिशानिर्देशों/अधिसूचना के अनुसार एआरआर प्राप्त कर सके। प्राधिकरण ऐसे प्रस्तावों पर आन-मैरिट विचार करेगा। समिति ने सृजित सुविधा के इष्टतम उपयोग के लिए रियायत प्रदाता प्राधिकारी द्वारा स्थिति की आवधिक समीक्षा की भी सिफारिश की है।

4.5. एमओएस के पत्र का पैरा 7 महापत्तनों को उक्त प्रक्रिया को सृजित सुविधा के इष्टतम प्रयोग के लिए स्थिति की आवधिक समीक्षा को अपनाने का निदेश देता है।

4.6. एमओएस के उक्त पत्र का हवाला देते हुए, डीपीटी ने पीपीपी मोड में विकसित की जाने वाली कांडला पत्तन के तूना के निकट टेकरा में शुष्क ब्लक कार्गो के लिए इस प्राधिकरण द्वारा 17 अगस्त, 2010 के अप्रेंट प्रशुल्क आदेश संख्या टीएमपी/42/2009-केपीटी के द्वारा महापत्तनों में पीपीपी परियोजनाओं के अप्रेंट प्रशुल्क निर्धारण दिशानिर्देशों के अनुसार और बीओटी प्रचालक एकेबीटीपीएल के नाम से अधिसूचित दरमानों में अनुमोदित भंडारण प्रशुल्क में संशोधन का प्रस्ताव दायर किया है। डीपीटी ने एकेबीटीपीएल के साथ परामर्श करके भंडारण प्रभारों के यौक्तिकीकरण के लिए एक उपयुक्त प्रस्ताव के साथ संशोधन/आशोधन/परिवर्तन के लिए 06 दिसंबर, 2019 को आयोजित न्यासी मंडल की बैठक के बोर्ड के संकल्प की प्रति भी प्रेषित की है, ताकि रियायत करार के अनुच्छेद 21.9 में उपलब्ध उपबंधों के अंतर्गत प्राधिकरण के दिशानिर्देशों/अधिसूचना के अनुसार एआरआर की प्राप्ति की जा सके।

4.7. डीपीटी ने 7 जनवरी 2010 के अपने पत्र के द्वारा डीपीटी द्वारा अपने न्यासी मंडल को प्रस्तुत की गई कार्य सूची टिप्पणियों की पृष्ठ संख्या का हवाला भी दिया है जिसमें यह दर्शाने के लिए आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत किए हैं कि विषयक परियोजना को एमओएस के 11 जुलाई 2018 के पत्र के अनुसार “तंगहाल परियोजना” के रूप में वर्गीकृत करने के तीनों प्रतिमानों को पूरा करती है।

- (क). (i). डीपीटी के यातायात विभाग द्वारा जारी कार्गो प्रहस्तन प्रमाणपत्रों के अनुसार वर्ष 2016-17 में 4.45 एमएमटी और वि.व 2017-18 में 4.2 एमएमटी कार्गो प्रहस्त किया गया। डीपीटी के यातायात विभाग द्वारा जारी कार्गो प्रहस्तन प्रमाणपत्रों की प्रतियां भी डीपीटी के प्रस्ताव के साथ संलग्न हैं।
- (ii). पिछले 2 वित्तीय वर्षों में हुई रोकड़ हानि यानी वि.व 2016-17 में 3,374.32 लाख रु. और वित्तीय वर्ष 2017-18 में, 5,566.75 लाख रु. है। रोकड़ हानि के आंकड़े एकेबीटीपीएल के सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित हैं (प्रति संलग्न)।
- (iii). प्रचालन अवधि के दौरान वर्ष वार रोकड़ हानि और नेट-वर्थ के विवरण का लेखापरीक्षक के प्रमाणपत्र वि.व 2014-15 से वि.व 2017-18 के लिए, टिप्पणियों के साथ, नीचे दिया जाता है:-

(रु. लाखों में)

वर्ष	रोकड़ हानि (देखें नीचे टिप्पणी 2)	नेट वर्थ	निवल हानि
2014-15	नीचे टिप्पणी 3	1,420.30	-580.42
2015-16	नीचे टिप्पणी 3	-4,022.20	-15,442.50
2016-17	-3,374.32	-13,137.74	-9,130.13
2017-18	-5,566.75	-24,531.42	-11,393.68

लेखापरीक्षक द्वारा जारी प्रमाणपत्र में टिप्पणियां:

- (i). कंपनी ने अपना वाणिज्यिक प्रचालन 17 मार्च, 2015 को आरंभ किया और तदनुसार, निवल हानि और नेट-वर्थ पर 2014-15 से आगे सुविचार किया गया है।
- (ii). रोकड़ हानि = कुल समग्र आय + मूल्यहास और परिशोधन व्यय।
- (iii). कंपनी को 17 जुलाई 2018 के डीपीटी से प्राप्त पत्र के निबंधन में रोकड़ हानि ब्यौरा पिछले 2 वित्तीय वर्षों का ही अपेक्षित है।

5. उक्त स्थिति को देखते हुए और विशाखापट्टणम पत्तन न्यास (वीपीटी) अर्थात् विज्ञाग जनरल कार्गो बर्थ प्राइवेट लिमिटेड (वीजीसीबीपीएल) और अदानी विज्ञाग कोल टर्मिनल प्रा.लि. (एवीसीटीपीएल) की अन्य दो “तंगहाल परियोजनाओं” के इसी प्रकार के प्रस्तावों पर अंतिम आदेश के लंबित रहने तक सिद्धांत रूप में दिये गए अनुमोदन को सुविचार में लेते हुए इस प्राधिकरण ने, अंतिम निर्णय के अधीन, डीपीटी के प्रस्ताव पर 20 फरवरी 2020 को तदर्थ अनुमोदन दे दिया था क्योंकि अंतिम निर्णय हितधारकों के साथ निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के पूरा होने के पश्चात् ही लिया जा सकता है। इसकी संसूचना डीपीटी को हमारे 24 फरवरी 2020 के पत्र के द्वारा दे दी गई थी।

6. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, डीपीटी के 21/23 दिसंबर, 2019 के प्रस्ताव और बाद में 07 जनवरी, 2020 के पत्र की एक प्रति 13 जनवरी, 2020 और 22 जनवरी 2020 को संबंधित हितधारकों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजी गई थी। हमें केवल इंडियन नैशनल शिपआनर्स एसोसिएशन (आईएनएसए) से टिप्पणियां प्राप्त हुईं जिन्हें फीडबैक सूचना के तौर पर डीपीटी के भेज दिया गया। डीपीटी ने 16 मार्च, 2020 के अपने ई-मेल के द्वारा उन पर अपना उत्तर दिया।

7. इस मामले में 12 मार्च, 2020 को डीपीटी परिसर में एक संयुक्त सुनवाई का आयोजन किया गया। डीपीटी ने अपने प्रस्ताव का संक्षिप्त पाँवर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया। संयुक्त सुनवाई में डीपीटी और संबंधित प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों ने अपने अपने निवेदन रखे।

8.1. डीपीटी के न्यासी मंडल ने इस बात पर सुविचार करने के पश्चात् कि यह परियोजना “तंगहाल परियोजना” घोषित किये जाने के लिए निर्धारित 3 प्रतिमानों को पूरा करती है, 11 जुलाई 2018 से भंडारण प्रभारों के यौक्तिकीकरण का अनुमोदन किया है।

8.2. डीपीटी ने 17 अगस्त, 2010 के अपफ्रंट प्रशुल्क आदेश के संदर्भ में भंडारण प्रभार का यौक्तिकीकरण का प्रस्ताव किया है। डीपीटी ने लागू सूचकांकन के पश्चात् वर्तमान में संशोधित भंडारण प्रभार निकालने के लिए लागू सूचकांकन कारक के साथ संशोधित भंडारण प्रभारों को अद्यतन नहीं किया है। अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 के अंतर्गत लागू सूचकांकन कारक के अनुसार संचयी सूचकांकन 25.67% जो 1 जनवरी, 2010 के आधार वर्ष के लिए वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए सूचकांकन कारक क्रमशः 2.07% और 2.56% है। इस प्राधिकरण द्वारा 17 अगस्त 2010 के अपफ्रंट प्रशुल्क आदेश में अनुमोदित भंडार प्रभार और 2 जनवरी, 2015 के आदेश में एकेबीटीपीएल के नाम से अधिसूचित भंडारण प्रभारों डीपीटी द्वारा प्रस्तावित संशोधित यौक्तिकीकृत भंडारण प्रभार और इस प्राधिकरण द्वारा सूचकांकन कारक लागू करने के पश्चात् आयात/निर्यात कार्गो के लिए तदर्थ आधार पर अनुमोदित संशोधित यौक्तिकीकृत भंडारण प्रभारों की तुलनात्मक स्थिति इस प्रकार है:-

- (i). **17 अगस्त 2010 के प्रशुल्क आदेश संख्या टीएएमपी/42/2009-केपीटी में निर्धारित भंडारण प्रभार:**

(दर रु. में प्रति एमटी प्रति दिन)

वस्तु	1वें से 10वें दिन तक दर	11वें दिन से 20वें दिन तक दर	21वें दिन से आगे दर
सभी प्रकार का कार्गो	2.07	4.14	6.21

- (ii). एकेबीटीपीएल के नाम से 02 जनवरी, 2015 के प्रशुल्क आदेश संख्या टीएमपी/59/2014-केपीटी में अधिसूचित सूचकांकित भंडारण प्रभार

(दर रु. में प्रति एमटी प्रति दिन)

वस्तु	1वें से 10वें दिन तक दर	11वें दिन से 20वें दिन तक दर	21वें दिन से आगे दर
सभी प्रकार का कार्गो	2.54	5.07	7.61

- (iii). 17 अगस्त, 2010 के मूल प्रशुल्क आदेश के हवाले से डीपीटी द्वारा प्रस्तावित संशोधित यौक्तिकीकृत भंडारण प्रभार

(दर रु. में प्रति एमटी प्रति दिन)

वस्तु	1 से 10वें दिन तक दर	11वें दिन से 20वें दिन तक दर	21वें दिन से आगे दर
सभी प्रकार का कार्गो	₹0.29	₹0.57	₹0.86

- (iv). डीपीटी द्वारा प्रस्तावित संशोधित यौक्तिकीकृत भंडार प्रभार जिन्हें प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन की तारीख को दर निकालने के लिए लागू सूचकांकित कारक के साथ (25.67%+ 2.07%+2.56%) सूचकांकित

(दर रु. में प्रति एमटी प्रति दिन)

वस्तु	1वें से 10वें दिन तक दर	11वें दिन से 20वें दिन तक दर	21वें दिन से आगे दर
सभी प्रकार का कार्गो	₹0.38	₹0.75	₹1.13

9. जैसा पहले बताया गया है, डीपीटी ने अपने 21 दिसंबर, 2019 के प्रस्ताव में भंडार प्रभारों के यौक्तिकरण का प्रस्ताव किया है। डीपीटी द्वारा प्रस्तावित दर 17 अगस्त 2010 के अपफ्रंट भंडारण प्रशुल्क के संदर्भ से है। डीपीटी ने लागू सूचकांकन के पश्चात् संशोधित भंडारण प्रभार निकालने के लिए यौक्तिकीकरण (यानी घटी हुई दर) भंडारण प्रभारों के संदर्भ से सूचकांकन कारक लागू नहीं किया है। संयुक्त सुनवाई के पश्चात्, डीपीटी ने 13 मार्च 2020 के अपने ई-मेल के द्वारा सूचकांकन कारक लागू करने के पश्चात् निशुल्क अवधि से इतर यौक्तिकीकृत सूचकांकित भंडारण प्रभारों का प्रस्ताव भेजा जो निम्नवत् है:-

संशोधित प्रस्तावित प्रशुल्क से लागू	1वें दिन से 10वें दिन तक दर	11वें दिन से 20वें दिन तक दर	21वें दिन से दर
11.07.2018 से 31.07.2018	0.36	0.73	1.09
01.08.2018 से 31.03.2019	0.37	0.74	1.12
01.04.2019	0.38	0.76	1.14

10. इस मामले में परामर्श संबंधी कार्रवाई इस प्राधिकरण के कार्यालयी रिकॉर्ड में उपलब्ध है। संबंधित पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों का सार उनको पृथक् रूप से प्रेषित किया जाएगा। ये विवरण हमारी वेबसाइट <http://tariffauthority.gov.in> पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

11. मामले के संसाधन के दौरान एकत्र की गई सूचना की समग्रता के आधार पर निम्नलिखित सूचना उभर कर सामने आती है:

- (i). दीनदयाल पत्तन न्यास (डीपीटी) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में सभी महापत्तन न्यासों को तंगहाल पीपीपी परियोजनाओं के संबंध में पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) द्वारा जारी 11 जुलाई 2018 के पत्र संख्या पीडी-13/1/2018-पीपीपी एकक के अनुपालन में अप्रेंट प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 द्वारा शासित के अंतर्गत डीपीटी के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के अंतर्गत निर्माण, प्रचालन और अंतर्गत (बीओटी) आधार पर बीओटी प्रचालक मैसर्स अदानी कांडला बल्क टर्मिनल प्रा.लि. (एकेबीटीपीएल) कांडला बल्क टर्मिनल प्रा.लि. (एकेबीटीपीएल) कांडला क्रीक के बाहर तुना के निकट टेकरा में शुष्क बल्क टर्मिनल के विकास के लिए दरमान की अधिसूचना करते हुए 02 जनवरी 2015 के आदेश संख्या टीएएमपी/59/2014-केपीटी के द्वारा इस प्राधिकरण द्वारा तुना के निकट टेकरा में शुष्क बल्क टर्मिनल के लिए भंडार प्रभारों के सूचकांकित अप्रेंट प्रशुल्क के यौक्तिकीकरण के लिए इस प्राधिकरण का अनुमोदन चाहा है।
- (ii). जैसा कि पहले के पैराओं में चर्चा की गई है, इस प्राधिकरण ने अप्रेंट प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 के अंतर्गत डीपीटी के साथ पीपीपी मॉडल अंतर्गत बीओटी आधार पर कांडला क्रीक के बाहर तुना के निकट टेकरा में विकसित शुष्क बल्क टर्मिनल के लिए 17 अगस्त, 2010 के आदेश संख्या टीएएमपी/42/2009-केपीटी के द्वारा अप्रेंट प्रशुल्क निर्धारित किये थे।  
डीपीटी ने परियोजना एकेबीटीपीएल को अवार्ड को/ दिशानिर्देशों के उपबंधों के अनुपालन में दरमान 17 अगस्त, 2010 के प्रशुल्क आदेश में इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अधिसूचित अप्रेंट प्रशुल्क को सूचकांकित करने के पश्चात् 2 जनवरी 2015 के आदेश संख्या टीएएमपी/59/2014-केपीटी के द्वारा एकेबीटीपीएल के नाम से अधिसूचित किये गए।
- (iii). डीपीटी के वर्तमान प्रस्ताव को इस लिए संसाधन के लिए गया क्योंकि यह तंगहाल परियोजना के संबंध में एमओएस के 11 जुलाई 2018 के पत्र के अनुपालन में दायर किया गया है।
- (iv). एमओएस ने अपने 11 जुलाई, 2018 के पत्र में पीपीपी परियोजनाओं के महापत्तन न्यासों द्वारा तंगहाल परियोजना के रूप में वर्गीकृत करने के लिए तीन प्रतिमान निर्धारित किये हैं जैसा ऊपर पैरा 7.2 में चर्चा की गई है और इसलिए इसे दोहराया नहीं जाता। डीपीटी के न्यासी मंडल ने एकेबीटीपीएल द्वारा संचालित परियोजना को तंगहाल परियोजना के रूप में घोषित किया है। पत्तन ने एकेबीटीपीएल की परियोजना को तंगहाल परियोजना के रूप में घोषित करने के लिए डीपीटी के न्यासी मंडल द्वारा एमओएस के पत्र में निर्धारित तीन प्रतिमानों पर सुविचार किये जाने के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुत किया है।

(क). जहां तक प्रथम प्रतिमान का संबंध है, डीपीटी द्वारा प्रस्तुत पिछले दो वर्षों का क्षमता उपयोग 70% से कम है, जैसा डीपीटी ने प्रदर्श किया है, नीचे सारणीबद्ध है:-

वर्ष	प्रहस्त कार्गो (एमएमटी)
2016-17	4.45
2017-18	4.20

[पत्तन ने प्रतिशत के हवाले से क्षमता उपयोगिता प्रस्तुत नहीं की है। तथापि, पत्तन ने बताया है कि इस परियोजना को इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अप्रेंट प्रशुल्क के अनुसार 14.112 एमटीपीए की क्षमता के साथ बीओटी आधार पर डीपीटी स्थित एकेबीटीपीएल को अवार्ड किया गया था। एकेबीटीपीएल द्वारा पिछले दो वर्षों में प्रहस्त यातायात पर क्षमता उपयोग वर्ष 2016-17 में 31.53% और वर्ष 2017-18 में 29.76% निकलता है, जैसा ऊपर दिया गया है, अर्थात् क्षमता उपयोग 70% से कम है।]

- (ख). जहां तक अन्य दो प्रतिमानों का संबंध है, पत्तन ने एकेबीटीपीएल के लेखापरीक्षकों से चार्टरित लेखाकार का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें पिछले 2 वित्तीय वर्षों के लिए एकेबीटीपीएल की रोकड़ हानियों और नेट-वर्थ को प्रमाणित किया गया है, जैसा नीचे सारणीबद्ध है:-

(रु. लाख में)

वर्ष	रोकड़ हानियां	नेट-वर्थ	निवल हानि
2014-15	प्रस्तुत नहीं	1,420.30	-580.42
2015-16	प्रस्तुत नहीं	-4,022.20	-15,442.50
2016-17	-3,374.32	-13,137.74	-9,130.13
2017-18	-5,566.75	-24,531.42	-11,393.68

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में 33.74 करोड़ रु. और वर्ष 2017-18 में 55.67 करोड़ रु. की रोकड़ हानि हुई है। इसके अतिरिक्त, एकेबीटीपीएल की नेट वर्थ वर्ष 2016-17 में (-)131.38 करोड़ रु. तक नकारात्मक थी जो वर्ष 2017-18 में नकारात्मक रूप से बढ़ कर (-)245.31 करोड़ रु. हो गई जो किसी परियोजना को तंगहाल परियोजना के रूप में घोषित करने के प्रतिमानों में से एक है और इसमें 50% से अधिक का नुकसान हुआ है।

- (v). (क). डीपीटी के न्यासी मंडल ने इस बात पर सुविचार करने के पश्चात् कि यह परियोजना 'तंगहाल परियोजना' के रूप में घोषित किये जाने के लिए निर्धारित तीनों प्रतिमानों को पूरा करती है, 11 जुलाई 2018 से भंडारण प्रभारों के यौक्तिकीकरण का अनुमोदन किया है। क्षमता के 70% से भी कम उपयोग का डीपीटी ने समर्थन किया है और वर्ष 2016-17 तथा 2018-19 के दो वर्षों में रोकड़ हानि तथा नेट वर्थ में कम से कम 50% के क्षरण का समर्थन एकेबीटीपीएल द्वारा प्रस्तुत व्यवसायरत चार्टरित लेखाकार के प्रमाणपत्र ने किया है और इसे डीपीटी के न्यासी मंडल ने सुविचार में लिया है। इस पर भरोसा किया जाता है।

डीपीटी ने, परियोजना की तंगहाली दूर करने के लिए, एमओएस के निर्देशों के अनुसार, इस परियोजना के भंडारण प्रशुल्क के यौक्तिकीकरण का प्रस्ताव किया है। वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान परियोजना से कार्गो की वास्तविक निकासी के आधार पर और परियोजना के भंडारण के लिए परियोजना के मूल रूप से अनुमोदित प्रशुल्क के अनुसार 11.68 करोड़ रु. पर राजस्व अपेक्षा का समान बनाए रखते हुए डीपीटी द्वारा निशुल्क अवधि से इतर भंडारण के लिए प्रशुल्क निकाला गया है। डीपीटी ने यह दर्शाने के लिए प्रस्तावित यौक्तिकीकृत भंडारण प्रभार राजस्व आकलन भी निकाला है कि प्रस्तावित यौक्तिकृत भंडारण प्रभार शुल्क बल्क टर्मिनल के अप्रेंट प्रशुल्क निर्धारण से संबंधित 17 अगस्त 2010 के मूल प्रशुल्क आदेश

संख्या टीएएमपी/42/2009-केपीटी में भंडारण से एआरआर आकलन के साथ राजस्व का मिलान होता है। भंडारण के लिए प्रस्तावित प्रशुल्क का विस्तार से परिकलन भी डीपीटी द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो इस आदेश के पूर्व के पैरा में दर्शाया गया है इसलिए इसे यहां दोहराया नहीं जाता।

डीपीटी द्वारा दायर प्रस्ताव डीपीटी के न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित है और तंगहाल परियोजना के संबंध में एमओएस के 11 जुलाई 2018 के पत्र में निर्धारित तीनों प्रतिमानों को पूरा करता है और डीपीटी का प्रस्ताव डीपीटी की एक परियोजना को तंगहाली से उबारने में सहायता और उसका पुनरूद्धार करने के लिए है। इसलिये, यह प्राधिकरण डीपीटी द्वारा प्रस्तावित सूचकांकन यौक्तिकीकृत भंडारण प्रभार को अनुमोदित करने को प्रवृत्त है। डीपीटी द्वारा निकाले गए सूचकांकित यौक्तिकीकृत भंडारण प्रभार में दूसरे दशमलव बिंदु और हमारे द्वारा निकाले गए भंडारण प्रभार, लागू सूचकांकन कारक लागू करने के पश्चात् थोड़ा सा विचलन है। डीपीटी द्वारा प्रस्तावित सूचकांकित यौक्तिकीकृत भंडारण प्रभार को इस प्राधिकरण द्वारा घोषित सूचकांकन कारक पर सुविचार करते हुए उस हद तक सुधार दिया गया है।

- (vi). डीपीटी ने 21 दिसंबर, 2019 के अपने प्रस्ताव में यौक्तिकीकृत भंडारण प्रभार का अनुमोदन 11 जुलाई, 2018 से यानी एमओएस द्वारा तंगहाल पीपीपी परियोजनाओं के बारे में 11 जुलाई 2018 को पत्र जारी किये जाने की तारीख से। डीपीटी का प्रस्ताव 11 जुलाई, 2018 से पूर्वव्यापी प्रभाव से डीपीटी के न्यासी मंडल के अनुमोदन पर आधारित है।

साधारणतः यह प्राधिकरण दरों का अनुमोदन पूर्वव्यापी प्रभाव से नहीं करता है। यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि एमओएस के 11 जुलाई 2018 के पत्र में तंगहाल पीपीपी परियोजना के भंडारण प्रभारों को यौक्तिकीकरण को पूर्वव्यापी प्रभाव देने का कोई उपबंध नहीं किया गया है। जब इस संबंध में डीपीटी से सफ्टीकरण मांगा गया और अनुरोध किया गया कि इस प्राधिकरण द्वारा अपनायी जा रही सामान्य प्रथा के अनुरूप यौक्तिकीकृत दर के लिए उत्तरव्यापी प्रभाव से प्रस्ताव प्रस्तुत करे तो डीपीटी ने बताया कि भंडार प्रशुल्क के यौक्तिकीकरण के प्रस्ताव को प्रभावकारिता के प्रयोजना से पूर्वव्यापी न माना जाये और इसे 11 जुलाई 2018 से अनुमोदित किया जाये क्योंकि उस तारीख को तंगहाल परियोजना के लिए एमओएस द्वारा दिशानिर्देश/निदेश संसूचित किये गये थे।

जहां तक डीपीटी द्वारा प्रस्तावित यौक्तिकीकृत भंडारण प्रभारों के पूर्वव्यापी प्रभाव चाहने का संबंध है, संयुक्त सुनवाई की कार्यवाही की ओर ध्यान आकर्षित कराया जाना संगत होगा, जहां एकेबीटीपीएल ने बताया कि उन्होंने डीपीटी को 3 दिसंबर 2019 को एक बचनपत्र दिया है कि वह रियायत करार के अनुसार डीपीटी को 10 जुलाई 2018 तक (यानी 11 जुलाई 2019 से एक दिन पहले तक) अर्जित भंडारण प्रभार पर @25.09% राजस्व हिस्सा देगा जिसका परिकलन अनुमोदित अपफ्रंट प्रशुल्क ब्याज सहित, के अनुसार होगा तथा 11 जुलाई 2018 से एकेबीटीपीएल ने भंडारण प्रभार का राजस्व हिस्सा डीपीटी को इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित यौक्तिकीकृत भंडार प्रभार के आधार पर ब्याज सहित अथवा 2010 के प्राधिकरण के आदेश में निकाले गए भंडार प्रभार पर सुविचारित एआरआर पर जो भी अधिक हो देने का आश्वासन दिया है। डीपीटी ने भी इस स्थिति की पुष्टि की है और स्पष्ट तौर पर बताया है कि यह स्थिति तो पत्तन के लिए और एक एकेबीटीपीएल के लिए भी लाभ की स्थिति, चित्र भी मेरी पट्ट भी मेरी। डीपीटी ने आगे और बताया है कि एकेबीटीपीएल द्वारा इस वर्ष 2019-20 में 6.5 एमटीपीए प्राप्त करने की प्रत्याशा है और 2020-21 में 10 एमटीपीए यातायात प्रहस्त करने का प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव से इस तंगहाल परियोजना के पुनरूद्धार करने में सहायता मिलेगी और इस पहलू को डीपीटी द्वारा पोत परिवहन मंत्रालय को एक उपलब्धि के तौर पर दर्शाया गया है।

उक्त स्थिति को देखते हुए और इस बात को मान्य करते हुए कि डीपीटी के न्यायी मंडल ने 6 दिसंबर, 2019 के संकल्प के द्वारा 11 जुलाई 2018 के पूर्वव्यापी प्रभाव से भंडारण प्रभारों के यौक्तिकीकरण को अनुमोदित किया है, यह प्राधिकरण डीपीटी के प्रस्ताव को 11 जुलाई 2018 से एमओएस के पत्र की



तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव से 19 फरवरी 2020 तक अनुमोदित करता है, अर्थात् इस प्राधिकरण द्वारा दिये गए तदर्थ अनुमोदन तक डीपीटी द्वारा प्रस्तावित संशोधित यौक्तिकीकृत भंडारण प्रभार को मंजूरी दी जाती है।

- (vii). डीपीटी ने अपना मूल प्रस्ताव 2010 में निकाली गए दर, बिना सूचकांकन के, पर प्रस्तावित किया था और वार्षिक सूचकांकन के लिए एक टिप्पणी का प्रस्ताव किया था। तथापि, बाद में, डीपीटी ने सूचकांकित यौक्तिकीकृत भंडारण प्रभार का प्रस्ताव किया, जिसे निर्धारित किया जाना है, जो दूसरे दशमलव में हल्के से सुधार के साथ है। अतः दर के सूचकांकन के लिए डीपीटी द्वारा प्रस्तावित टिप्पणी असंगत हो जाती है।

यहां यह उल्लेख करना समीचीन है कि, डीपीटी द्वारा प्रस्तावित सूचकांकित संशोधित यौक्तिकीकरण भंडारण प्रभार वर्ष 2019-20 के लिए लागू सूचकांकन कारक को प्रग्रहण करता है। बीओटी प्रचालक 2008 के दिशानिर्देशों द्वारा शासित होता है, अतः वह इस प्राधिकरण द्वारा घोषित डब्ल्यूपीआई के 60% वार्षिक सूचकांकन के अंतर्गत शासित होता है। एकेबीटीपीएल अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 के अंतर्गत शासित है, और इसलिए वह 24 जुलाई 2019 के आदेश में अनुमोदित यौक्तिकीकृत संशोधित भंडारण प्रभार पर इस प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए घोषित वार्षिक सूचकांकन का पात्र है। वर्ष 2020-21 के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 के अंतर्गत डब्ल्यूपीआई के 60% पर सूचकांकन कारक 1.13% है। इसलिए सूचकांकित दर पर 1 अप्रैल 2020 से 19 फरवरी 2021 तक लागू 1.13% का सूचकांकन कारक को लागू करके निकाली जाये और तदनुसार अनुसूची में यौक्तिकीकृत भंडारण प्रभार शामिल कर लिया गया है।

- (viii). चूंकि डीपीटी का वर्तमान प्रस्ताव एक वर्ष की सीमिति अवधि के लिए है और यह मान्य करते हुए कि एकेबीटीपीएल के नाम से अधिसूचित दरमान में निर्धारित भंडारण प्रभार और निशुल्क अवधि, वार्षिक वृद्धि के अधीन, 30 वर्ष की संपूर्ण परियोजना अवधि के लिए है, इसलिए दरमानों की अनुसूची 4 में भंडारण प्रभार से संबंधित मौजूदा टिप्पणी (i) से (iii) को लागू करने में सरलता के लिए यहां अलग से निर्धारित की जाती हैं न कि इस प्राधिकरण द्वारा 2 जनवरी 2015 के आदेश संख्या टीएमपी/59/2014-केपीटी में एकेबीटीपीएल के नाम से मौजूदा दरमानों के साथ छेड़छाड़ की जाए।

- (ix). डीपीटी ने एक टिप्पणी का प्रस्ताव किया है कि प्रस्तावित यौक्तिकीकृत भंडारण प्रशुल्क की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष पश्चात् समीक्षा की जाये यानी प्रस्तावित प्रशुल्क आरंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा अथवा संशोधित प्रशुल्क का अनुमोदन, यदि कोई है, समीक्षोपरांत, जो भी बाद में हो इस संबंध में, यह कहना उचित होगा कि एमओएस के 11 जुलाई 2018 के पत्र के पैरा 6 के अनुसार सुग्राही प्राधिकारी सृजित सुविधा के इष्टतम उपयोग के लिए स्थिति की आवधिक समीक्षा करेगा। डीपीटी की अन्य तंगहाल परियोजनाओं के मामले में, डीपीटी ने यौक्तिकीकृत भंडारण प्रकार का अनुमोदन एक वर्ष की अवधि के लिए चाहा है और उसके बाद समीक्षा की जायेगी और इस प्राधिकरण द्वारा डीपीटी की दो तंगहाल डीपीटी परियोजनाओं के लिए सिद्धांत रूप में अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष के लिए अनुमोदित किया गया था। आसन्न मामले में, चूंकि इस प्राधिकरण द्वारा यौक्तिकीकृत भंडारण प्रभार को 20 फरवरी 2020 से तदर्थ आधार पर अनुमोदन दे दिया गया था, इसलिए इस प्राधिकरण द्वारा संशोधित भंडारण अनुसूची की वैधता उस तारीख से, जब तदर्थ अनुमोदन दिया गया था एक वर्ष के लिए 19 फरवरी, 2021 तक किया जाता है। इसके अतिरिक्त पहले दिये गए कारणों के आधार पर, डीपीटी का प्रस्ताव पूर्वव्यापी प्रभाव से अनुमोदन का है, अतः 11 जुलाई 2018 से, यानी एमओएस के पत्र की तारीख से, 19 फरवरी 2020 तक की अवधि, जिस तारीख को इस प्राधिकरण

द्वारा तदर्थ अनुमोदन दिया गया, अनुमोदित है। अतः, डीपीटी द्वारा प्रस्तावित टिप्पणी को इस प्रकार आशोधित किया जाता है कि यह 11 जुलाई 2018 से प्रभावी है और 19 फरवरी, 2021 तक वैध रहेगा।

12.1. परिणाम में और ऊपर दिये गए कारणों से, और सामूहिक विचार विमर्श के आधार पर एकेबीटीपीएल के नाम से अधिसूचित इस प्राधिकरण के 02 जनवरी, 2015 के आदेश संख्या टीएएमपी/59/2014-केपीटी में मौजूदा अनुसूची 4 को इसकी निर्धारित वैधता अवधि 19 फरवरी, 2021 तक निम्नलिखित अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:-

(रु. में प्रति टन प्रति दिन या उसका एक भाग)

क्र.सं.	विवरण	11.07.2018 से 19.02.2021 तक की अवधि के लिए संशोधित सूचकांकित भंडारण प्रभार		
		11.07.2018 से 31.03.2019 तक	वर्ष 2019-20 के लिए	01.04.2020 से 19.02.2021 तक की अवधि के लिए
1.	1 से 10वें दिन तक भंडारण प्रभार	0.37	0.38	0.39
2.	11वें से 20वें दिन तक भंडारण प्रभार	0.73	0.75	0.76
3.	21वें दिन से आगे भंडारण प्रभार	1.10	1.13	1.14

#### भाग 4 संबंधी टिप्पणी

- आयात नौभार के लिए पांच निशुल्क दिवसों तथा निर्यात नौभार हेतु 15 निशुल्क दिवसों की अनुमति होगी। निशुल्क अवधि के परिकलन के प्रयोजनार्थ सीमाशुल्क अवकाश दिवस तथा टर्मिनल के अकार्य दिवसों को शामिल नहीं किया जाएगा।
- निर्धारित निशुल्क दिनों के बाद कार्गो के ठहराव के लिए टर्मिनल के अकार्य दिवसों तथा सीमाशुल्क अधिसूचित अवकाश दिवस सहित सभी दिनों के लिए भंडारण प्रभार संदेय होगा।
- जब कभी प्रयोक्ता द्वारा यह अनुरोध किया जाए टर्मिनल प्रचालक को उत्तरदायी कारणवश टर्मिनल प्रचालक नौभार की सुपुर्दगी/ले जाने की स्थिति में नहीं है तब उस अवधि के लिए भंडारण प्रभार प्रोद्भूत नहीं होगा।
- उक्त भंडारण अनुसूची 11 जुलाई 2018 से अनुमोदित की जाती है और 19 फरवरी 2021 तक वैध रहेगी।

12.2. एकेबीटीपीएल को डीपीटी के माध्यम से प्रहस्तित कार्गो वार प्रमात्रा सहित तिमाही वास्तविक निष्पादन रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 15 दिन के भीतर और वित्तीय वर्ष के अंत में 2 माह के भीतर वास्तविक और वित्तीय दोनों ही के वार्षिक निष्पादन इस प्राधिकरण को प्रस्तुत करने का निदेश दिया जाता है।

टी.एस.बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[ विज्ञापन- III/4/असा./63/2020-21]

**TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS****NOTIFICATION**

Mumbai, the 10th June, 2020

**No.TAMP/64/2019-DPT** In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in pursuance of Ministry of Shipping letter No.PD-13/1/2018-PPP Cell dated 11 July 2018 on Stressed PPP Projects, the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from the Deendayal Port Trust (DPT) for rationalization i.e. reduction of indexed storage charges approved in the SOR for Dry Bulk Terminal developed by the BOT operator M/s.Adani Kandla Bulk Terminal Pvt. Ltd. (AKBTPL) on Build, Operate and Transfer (BOT) basis under Public Private Partnership (PPP) model with DPT as in the Order appended hereto.

**Tariff Authority for Major Ports****Case No.TAMP/64/2019-DPT****Deendayal Port Trust**

-----

**Applicant****QUORUM**

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)  
(ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

**ORDER**

(Passed on this 1st day of June 2020)

This case relates to a proposal dated 21 December 2019 received from the Deendayal Port Trust (DPT) in pursuance of the Ministry of Shipping (MOS) letter No.PD-13/1/2018-PPP Cell dated 11 July 2018 on “Stressed PPP Projects” for rationalisation of indexed upfront tariff for storage charges for Dry Bulk Terminal off Tekra near Tuna approved by the Authority vide Order No.TAMP/59/2014-KPT dated 02 January 2015 while notifying the SOR for Dry Bulk Terminal developed off Tekra near Tuna outside Kandla creek by the BOT operator M/s. Adani Kandla Bulk Terminal Pvt. Ltd. (AKBTPL) on Build, Operate and Transfer (BOT) basis under Public Private Partnership (PPP) model with DPT.

1.2. A copy of the said MOS letter dated 11 July 2018 on Stressed PPP Projects is attached by the DPT to its proposal dated 21 December 2019.

2. The main points made by the DPT in the proposal dated 21 December 2019 are as follows:

- (i). The Authority has passed the Order No.TAMP/42/2009-KPT dated 02 November 2010 vide Gazette No.285 notifying the upfront tariff for the project of development of Dry Bulk Terminal off Tekra near Tuna in accordance with the Upfront Tariff Guidelines of 2008.
- (ii). As per the aforesaid notified Order, the approved upfront tariff for storage, beyond free period, is as under:
- (A). **For Import / Export:**

Commodity	(Rate in ₹ per MT per Day)		
	Rate from 1 <sup>st</sup> day to 10 <sup>th</sup> day	Rate from 11 <sup>th</sup> day to 20 <sup>th</sup> day	Rate from 21 <sup>st</sup> day onward
All types of cargo	₹2.07	₹4.14	₹6.21

- (iii). Subsequently, DPT had entered into Concession Agreement with M/s.Adani Kandla Bulk Terminal Pvt. Ltd. (AKBTPL) on 27 June 2012 to develop the project on BOT basis for 30 years Concession Period. Subsequent to construction of the Project by the Concessionaire, the Project is currently under operation since 10 February 2015.
- (iv). MOS vide letter bearing no.PD-13/1/2018-PPP Cell dated 11 July 2018 alongwith Report (dated 4 April 2018) of the Committee chaired by Chairman, IPA, communicated to all the Major Port Trusts the Guidelines & Directives for removal of the Stress of the “Stressed Projects”.
- (v). As per the criteria for classification of a PPP project for ‘Stressed Project’ laid down in the MOS letter, the subject project is classified as a ‘Stressed Project’.
- (vi). Para 6 of the MOS letter bearing No.PD-13/1/2018-PPP Cell dated 11 July 2018 states-

*“The Committee headed by AS&FA, MOS is of the view that wherever such issue of abnormal storage charges emerges in stressed projects as defined in Para 3 above, the Ports may approach TAMP under the provision of “Amendments, modifications or alternations” to the terms and conditions of the concession agreement with an appropriate proposal for rationalization of storage charges in consultation with concessionaires so as to achieve the ARR as per the TAMP guidelines /notification. TAMP has to consider such proposals on merit. The Committee also recommended review of the situation by the Concessioneing Authority periodically for optimum utilization of the facility created.”*

- (vii). Accordingly, for removal of the stress of the Project, as per the MOS directive, it is proposed to rationalize the tariff for storage for this project. Based on the actual evacuation of cargo from this project, during the years 2015-16, 2016-17 and 2017-18 and by keeping the revenue requirement for storage for the project same as per the originally approved tariff for the project, the proposed tariff for storage, beyond free period, is worked out and the same is given below:

- (A). Average storage of cargo in different slab period based on actual evaluation in 3 years.

As per TAMP Order for TEKRA	₹ in Lakhs
Revenue Requirement as per approved TAMP Order	1168.70
Revenue Requirement in Amt. ₹	116870000

Particulars	2015-16	2016-17	2017-18	Total	Average
Total Dry Bulk Cargo	37,27,851.44	4456100.00	4205212.94	12389164.38	100%
Free Period	13,88,894.61	1350381.99	2008611.60	4747888.20	38.32%
1 <sup>st</sup> day to 10 <sup>th</sup> day after free period	7,14,302.28	1032021.31	502241.40	2248564.99	18.15%
11 <sup>th</sup> day to 20 <sup>th</sup> day after free period	567432.46	779791.50	517145.10	1864369.06	15.05%
21 <sup>st</sup> day to 30 <sup>th</sup> day after free period	442151.38	492321.26	445842.70	1380315.33	11.14%
31 <sup>st</sup> day to 40 <sup>th</sup> day after free period	341767.71	280367.64	256686.46	878821.80	7.09%
41 <sup>st</sup> day to 50 <sup>th</sup> day after free period	143820.48	197825.18	191029.57	532675.23	4.30%
51 <sup>st</sup> day to 60 <sup>th</sup> day after free period	53836.59	133618.25	88028.43	275483.27	2.22%
61 <sup>st</sup> day to 70 <sup>th</sup> day after free period	9054.52	148112.25	59323.12	216489.90	1.75%
71 <sup>st</sup> day to 80 <sup>th</sup> day after free period	43084.80	22167.89	40818.15	106070.84	0.86%
81 <sup>st</sup> day onwards after free period	23506.60	19492.74	95486.42	138485.76	1.12%

- (B). Period wise storage of cargo after free period:

Storage Cargo belonging to									Total	Assumed
81 <sup>st</sup> day onwards after free period	71 <sup>st</sup> day to 80 <sup>th</sup> day after free period	61 <sup>st</sup> day to 70 <sup>th</sup> day after free period	51 <sup>st</sup> day to 60 <sup>th</sup> day after free period	41 <sup>st</sup> day to 50 <sup>th</sup> day after free period	31 <sup>st</sup> day to 40 <sup>th</sup> day after free period	21 <sup>st</sup> day to 30 <sup>th</sup> day after free period	11 <sup>th</sup> day to 20 <sup>th</sup> day after free period	1 <sup>st</sup> day to 10 <sup>th</sup> day after free period	Stored	As Stored
1.12%	0.86%	1.75%	2.22%	4.30%	7.09%	11.14%	15.05%	9.07%	52.60%	1 <sup>st</sup> day to 10 <sup>th</sup> day after free period
1.12%	0.86%	1.75%	2.22%	4.30%	7.09%	11.14%	7.52%		36.00%	11 <sup>th</sup> day to 20 <sup>th</sup> day after free period

1.12%	0.86%	1.75%	2.22%	4.30%	7.09%	5.57%			22.91%	21 <sup>st</sup> day to 30 <sup>th</sup> day after free period
1.12%	0.86%	1.75%	2.22%	4.30%	3.55%				13.79%	31 <sup>st</sup> day to 40 <sup>th</sup> day after free period
1.12%	0.86%	1.75%	2.22%	2.15%					8.09%	41 <sup>st</sup> day to 50 <sup>th</sup> day after free period
1.12%	0.86%	1.75%	1.11%						4.83%	51 <sup>st</sup> day to 60 <sup>th</sup> day after free period
1.12%	0.86%	0.87%							2.85%	61 <sup>st</sup> day to 70 <sup>th</sup> day after free period
1.12%	0.43%								1.55%	71 <sup>st</sup> day to 80 <sup>th</sup> day after free period
0.56%									0.56%	81 <sup>st</sup> day onwards after free period

## (C). Slab Rate Calculation:

Existing Slab Rate for 1 <sup>st</sup> day to 10 <sup>th</sup> day after free period	2.07	X
Existing Slab Rate for 11 <sup>st</sup> day to 20 <sup>th</sup> day after free period	4.14	2x
Existing Slab Rate for 21 <sup>st</sup> day onwards	6.21	3x

## (D). Revised storage charge calculation:

(D). Revised storage charge calculation.				
1	Annual Revenue Requirement from storage activity as per approved TAMP Order No.TAMP/42/2009-KPT dated 17 August 2010 relating to fixation of upfront tariff for dry bulk terminal	₹11,68,70,000 (11.68 crores)	-	
2	Optimal capacity as per TAMP Order dated 17 August 2010 relating to fixation of upfront tariff for dry bulk terminal	1,41,12,000 (14.112 million tonnes p.a.)		
3	Quantity of cargo to be stored for 1 <sup>st</sup> to 10 <sup>th</sup> day after free period	52.60%*	X	7423246
4	Quantity of cargo to be stored for 11 <sup>th</sup> to 20 <sup>th</sup> day after free period	36.00%*	2X	14846492
5	Quantity of cargo to be stored from 21 <sup>st</sup> day and onwards after free period	54.58%*  (22.91% + 13.79% + 8.09% + 4.83% + 2.85% + 1.55% + 0.56%)*	3X	22269738
6	No. of days in a slab			10
7	Total optimal capacity to attract storage charge			44539476
8	Revised storage rate calculation for the first slab 1 <sup>st</sup> day to 10 <sup>th</sup> day after free period	=(116870000/14112000)/ * (44539476/10)		0.29
9	11 <sup>th</sup> day to 20 <sup>th</sup> day after free period	=0.29X2		0.57
10	21 <sup>st</sup> day onwards	=0.29X3		0.86

\* % of cargo availing storage after free period is arrived by DPT based on actual evacuation pattern for the years 2015-16 to 2017-18 for which detailed working given in Annex-A of the proposal by the DPT.

(E). Based on the revised calculation, the revised proposed storage charges after the prescribed free period is as follow:

For Import / Export:

(Rate in ₹ per MT per day)

Commodity	Rate from 1 <sup>st</sup> day to 10 <sup>th</sup> day	Rate from 11 <sup>th</sup> day to 20 <sup>th</sup> day	Rate from 21 <sup>st</sup> day onward
All types of cargo	₹0.29	₹0.57	₹0.86

- (viii). The computation of revenue estimation at the revised proposed storage charges matching with the ARR estimates to be recovered from storage charges in original upfront tariff Order dated 2 November 2010 is given below:

Particulars	% Qty.	Qty.	Rate for days per tonne per day	₹ in lakhs
<b>Total optimal cargo capacity as assessed in Original Order dated 17.8.2010</b>		14112000	10	-
1 <sup>st</sup> day to 10 <sup>th</sup> after free period	52.60%	7422912	0.29	215.26
11 <sup>th</sup> day to 20 <sup>th</sup> after free period	36.00%	5080320	0.57	289.58
21 <sup>st</sup> day to 30 <sup>th</sup> after free period	22.91%	3233059	0.86	278.04
31 <sup>st</sup> day to 40 <sup>th</sup> after free period	13.90%	1961568	0.86	168.70
41 <sup>st</sup> day to 50 <sup>th</sup> after free period	8.09%	1141661	0.86	98.18
51 <sup>st</sup> day to 60 <sup>th</sup> after free period	4.83%	681610	0.86	58.12
61 <sup>st</sup> day to 70 <sup>th</sup> after free period	2.85%	402192	0.86	34.59
71 <sup>st</sup> day to 80 <sup>th</sup> after free period	1.55%	218736	0.86	18.81
81 <sup>st</sup> day to 90 <sup>th</sup> after free period	0.56%	79027	0.86	6.80
<b>Total Revenue</b>				<b>1168.58</b>

[Arithmetical errors corrected]

- (ix). On the request of DPT vide its letter dated 31 January 2019, M/s.AKBTPPL vide its letter dated 01 February 2019 has furnished the consent to the proposed revised tariff for storage.
- (x). The revised calculations for the proposed tariff for storage were also presented in detail and discussed in the Board of DPT in its meeting held on 06 December 2019. Based on that, the Board has resolved vide Resolution No.94 to approve the above proposed rationalisation of storage tariff for the project. The DPT Board of Trustees in the meeting held on 06 December 2019 has resolved the following points:
- (a). In consistence with directives of the MOS letter dated 11 July 2018, the Board resolves to approve the rationalized tariff of Storage Charges (achieving the ARR as per already approved TAMP Notification) based on the actual evacuation of cargo from the project during the years 2015-16, 2016-17 and 2017-18 as given below:

Reference	(₹ per MT per day)		
	Rate from 1 <sup>st</sup> day to 10 <sup>th</sup> day	Rate from 11 <sup>th</sup> day to 20 <sup>th</sup> day	Rate from 21 <sup>st</sup> day onwards
Revised proposed tariff	₹0.29	₹0.57	₹0.86

The above tariff will be indexed to inflation of 60% of variation in WPI occurring between 01 January 2010 and 1<sup>st</sup> January of relevant year.

- (b). To approach TAMP for approval of the above proposed rationalized tariff of Storage Charges as per the directive issued by MOS provided under its letter dated 11 July 2018. Also, to send the submission of AKBTPPL vide letter dated 01 February 2019 to TAMP alongwith the Tariff proposal for storage;
- (c). The proposed Rationalized Tariff for storage will be effective from 11 July 2018;
- (d). The proposed Rationalized Tariff for storage will be reviewed after one year from date of Notification i.e., the proposed tariff will be effective for initial period of one year or approval of revised tariff, if any, post review whichever is later.

- (xi). In view of above and in consistence with directives of the MOS letter dated 11 July 2018, DPT requests the Authority to approve the following revised proposed tariff for storage beyond the prescribed free period:

(A). **Import / Export:**

(Rate in ₹ per MT per day)

Commodity	Rate from 1 <sup>st</sup> day to 10 <sup>th</sup> day	Rate from 11 <sup>th</sup> day to 20 <sup>th</sup> day	Rate from 21 <sup>st</sup> day onwards
All types of cargo	₹0.29	₹0.57	₹0.86

- (a). The above tariff will be indexed to inflation of 60% of variation in WPI occurring between 01 January 2010 and 1<sup>st</sup> January of relevant year.
- (b). The proposed Rationalized Tariff for storage will be effective from 11 July 2018.
- (c). The proposed Rationalized Tariff for storage will be reviewed after one year from date of Notification i.e., the proposed tariff will be effective for initial period of one year or approval of revised tariff, if any, post review whichever is later.

3.1. Since there were gaps in proposal of DPT dated 21 December 2019, the DPT was vide our letter dated 3 January 2020 requested to furnish requisite information/ documents on a few points. In response, the DPT vide its email dated 07 January 2020 has furnished its reply to us. Based on submissions of DPT vide its letter dated 07 January 2020, as regards seeking retrospective revision of proposed SOR from 11 July 2018, while acknowledging the proposal, DPT was vide our letter dated 13 January 2020 requested to furnish further clarification on the said matter. The DPT has responded vide its letter dated 23 January 2020.

3.2. A summary of the information/ document sought by us and reply furnished by DPT are tabulated below:

Sr. No.	Information / documents sought by us	Reply furnished by DPT
(i).	Requisite details with documentary evidence to establish that said project fulfils the 3 criteria prescribed in the MOS letter dated 11 July 2018 in para 3 read with 6 for categorization of PPT Project as "Stressed Project".	The documentary evidence establishing that subject project is fulfilling 3 criteria as per MOS letter dated 11 July 2018 towards categorization as "Stressed Project" are furnished which is brought out in subsequent paragraph. [Refer Page Nos.597-604 of Agenda item No.29 of DPT's Board Meeting held on 06 December 2019.]
(ii).	The said details to be substantiated by a Certificate from a practicing Chartered Accountant certifying the requisite details as per para 3 (ii) and (iii) of the MOS letter for categorization of the said PPP Project as Stressed Project by the DPT. This is in line with the approach followed by other Major Port Trusts as well like VPT who had filed proposal in pursuance of MOS letter dated 11 July 2018.	A certificate issued by the Chartered Accountant certifying Cash Loss, Net Loss and Net Worth for the details as per para 3 (b) and 3 (c) of MOS letter dated 11 July 2018 is furnished which is brought out in subsequent paragraph. [Refer Page Nos.602-604 of Agenda Item No.29 of DPT's Board Meeting held on 06 December 2019.]
(iii).	Approval of Board of Trustees of DPT for categorization of the said PPP project as Stressed Project based on the 3 criteria prescribed in the MOS letter dated 11 July 2018.	In the DPT's letter dated 23 December 2019, by enclosing the resolution No.94 of Board Meeting dated 06 December 2019, it was submitted that the proposed rationalization of storage tariff for the project has been approved by Board of DPT. The aforesaid approval of the Board is on the proposal submitted under Agenda item no.29 (copy furnished). Under the Agenda item by submitting the documents specified in response to the above observations as Sr. Nos.1 & 2 and by furnishing the detailed examination of such documents by Transaction Advisor of DPT for PPP Projects [Page Nos.605-607 of Agenda item no.29 submitted by DPT to its Board], it was submitted to Board of Trustees of DPT that the subject project fulfills the criteria(s) as specified by MOS vide its directives dated 11 July 2018, hence, the subject

		<p>project is classified as “Stressed Project” [para 19.1 at Page No.552 of Board Agenda item No.29 submitted by DPT to its Board.]</p> <p>By considering above, the Board of Trustees of DPT has approved the proposal of rationalization of Storage tariff. By this it is construed that the Board of Trustees of DPT has also approved categorization of the subject PPP Project as “Stressed Project” based on the 3 criteria prescribed in the MOS letter dated 11 July 2018.</p>
(iv).	<p>(a). The DPT proposal dated 21 December 2019 in concluding paragraph states that proposed Rationalized storage Tariff will be effective from 11 July 2018 i.e. DPT seeks retrospective amendment from 11 July 2018. It is relevant here to state that the said MOS letter dated 11 July 2018 does not contain any provision for retrospective effect of rationalisation in storage charges of Stressed PPP project. The DPT to suitably amend its proposal for considering it prospectively.</p>	<p>The proposal of rationalization of Storage Tariff for the Project will be effective from 11 July 2018, the date on which the MOS have communicated the Guidelines/ directives for “Stressed Project”, viz., removal of stress including of rationalization of storage charges of Stressed PPP Projects. Hence, the subject proposal of DPT towards rationalization of storage tariff may not be construed as retrospective for the purpose of its effectiveness.</p> <p>Accordingly, as approved by DPT Board, the proposed rationalization of Storage Tariff is approved w.e.f. 11 July 2018, the date on which the MOS has communicated the Guidelines/ directives for Stressed Project.</p>
	<p>(b). With reference to the above submission, the DPT is requested to give reference to the relevant para in the MOS letter dated 11 July 2018 prescribing that proposal of Major Port Trusts for rationalisation in storage tariff for Stressed PPP Project shall come into effect from 11 July 2018 (i.e. retrospective effect as far as DPT proposal filed in January 2020 is concerned)</p>	<p>The DPT has vide its letter dated 22 January 2020 has clarified that in general, the directives of issuing Authority become effective / come into force from the date of issuing such directives until otherwise specifically mentioned about date of its effectiveness in the directives itself.</p> <p>In the instant case, as the MOS directives dated 11 July 2018 does not spell specific date of effectiveness of the directives, the present proposal of rationalization of storage tariff for the project will be effective from 11 July 2018, the date on which the MOS have communicated the Guidelines / directives for Stressed project. Hence, the subject proposal of DPT towards rationalization of storage tariff may not be construed as retrospective for the purposed of its effectiveness.</p> <p>Accordingly, as approved by DPT Board, the proposed rationalization of Storage Tariff is approved w.e.f. 11 July 2018, the date on which the MOS have communicated the Guidelines / directives for Stressed project.</p>

4.1. As stated by the DPT, the MOS vide its e-mail dated 11 July 2018 has issued the letter No.PD-13/1/2018-PPP Cell dated 11 July 2018 regarding Stressed PPP project along with copy of report of the Committee chaired by Chairman, IPA on the issues pertaining to Stressed PPP projects

4.2. The said letter of MOS at Para 3 states that the MOS has formed a Committee under the chairmanship of Chairman IPA to take timely decision on port issues i.e. stressed PPP project and issues such as MGT, Permissions, Port charges, Storage charges etc. of PPP users. The said committee after detailed examination of various issues including the issue of storage charges faced in the PPP projects of various major ports has submitted its report to the MOS. The said Committee has recommended the following criteria for classification of PPP project as “**Stressed Projects**”:



- (a). The project is sub optimally utilised as evidenced by the actual cargo handled by the operator during two preceding financial years being less than 70% of the projection as per DPR/Feasibility report forming part of the bid document and
- (b). Project SPV incurring cash loss continuously for two preceding financial years and
- (c). That the losses incurred by concessionaire has caused atleast 50% erosion of its peak Net Worth during the operation period.

4.3. The MOS has, subsequently, formed a Committee under the Chairmanship of AS&FA, MOS alongwith JS (P) and Chairmen of DPT, VPT and KOPT for examination of IPA Report for suggesting future course of action.

4.4. Para 6 of the MOS letter dated 11 July 2018 addressed to all Major Port Trusts states that whenever issue of abnormal storage charges emerges in stressed projects as defined in the MOS letter, the Ports may approach TAMP under the provisions of "Agreements, modification or alternations" to the terms and conditions of the concession agreement with an appropriate proposal for rationalization of storage charges in consultation with concessionaire so as to achieve the ARR as per the TAMP guidelines / notification. TAMP has to consider such proposal on merit. The Committee also recommended review of the situation by the Concessioneing Authority periodically for optimum utilization of the facility created.

4.5. Para 7 of the MOS letter states that the Major Ports are directed to adopt the aforesaid procedure including review of the situation periodically for optimum utilization of the facility created.

4.6. Referring to the said letter of MOS, the DPT has filed the current proposal for amendment in the storage schedule approved by the Authority in upfront tariff Order No.TAMP/42/2009-KPT dated 17 August 2010 for the Dry Bulk Terminal off Tekra near Tuna at Port of Kandla to be developed under PPP mode in accordance with the guidelines for upfront tariff setting for PPP projects at Major Ports and notify the SOR in the name of BOT operator AKBTPL. The DPT has furnished a copy of board resolution of its Trustees held on 06 December 2019 proposing for amendment/ modification/ alteration with an appropriate proposal for rationalization of storage charges in consultation with AKBTPL so as to achieve the ARR as per the TAMP guidelines/ notification under the provisions available at Article 21.9 of the Concession Agreement.

4.7. The DPT vide its letter dated 7 January 2020 has drawn reference to the relevant Page Nos of the Agenda note submitted by the DPT to its Board of Trustees, wherein necessary documents are submitted to show that subject project is fulfilling 3 criteria as per MOS letter dated 11 July 2018 for categorization of the project as "Stressed Project":

- (A). (i). Cargo handled as per the Cargo Handling Certificates issued by DPT's Traffic Department in FY 2016-17 is 4.45 MMT and in FY 2017-18 is 4.2 MMT. Copies of cargo handling certificates issued by DPT's Traffic Department are furnished along with the proposal by the DPT.
- (ii). Cash loss incurred for 2 preceding financial years i.e. FY 2016-17 is `3,374.32 lakhs and for FY 2017-18 is `5,566.75 lakhs. The cash loss figures are certified by AKBTPL's Statutory Auditor (copy furnished).
- (iii). Auditor's certificate giving the statement of year-wise cash loss and net worth during the operation period furnished for the financial years 2014-15 to FY 2017-18 along with the notes are given below:

(₹ in lakhs)

Year	Cash Loss (Refer note 2 below)	Net Worth	Net Loss
2014-15	Note 3 below	1,420.30	-580.42
2015-16	Note 3 below	-4,022.20	-15,442.50
2016-17	-3,374.32	-13,137.74	-9,130.13
2017-18	-5,566.75	-24,531.42	-11,393.68

Notes in the Certificate issued by the Auditor:

- (i). The Company started its commercial operations from 17 March 2015 and accordingly, net loss and net worth have been considered from 2014-15 onwards
- (ii). Cash Loss = Total Comprehensive Income+ Depreciation and Amortization Expense

- (iii). In terms of letter from DPT dated July 17, 2018 to the company, the cash loss details are required for preceding two financial years.

5. In view of the above position and considering that in principle approval for similar proposal of other two stressed projects of Visakhapatnam Port Trust (VPT) viz., Vizag General Cargo Berth Pvt. Ltd. (VGCBPL) and Adani Vizag Coal Terminal Pvt. Ltd. (AVCTPL) was approved pending final order, this Authority granted adhoc approval to the proposal of the DPT on 20 February 2020 subject to final decision of this Authority after completion of prescribed consultation process with stakeholders was communicated to the DPT vide our letter dated 24 February 2020.

6. In accordance with the prescribed consultation process, a copy of DPT proposal dated 21/23 December 2019 and subsequent DPT letter dated 07 January 2020 was forwarded to the concerned stakeholders on 13 January 2020 and on 22 January 2020 for their comments. We have received comments only from Indian National Shipowners Association (INSA) which was forwarded to DPT as feedback information. The DPT vide its email dated 16 March 2020 have furnished its reply.

7. A joint hearing in this case was held on 12 March 2020 at the DPT premises. The DPT made a brief Power Point presentation of its proposal. At the joint hearing, the DPT and the concerned users/ user organizations have made their submissions.

8.1. The Board of Trustees of DPT has approved the rationalised storage charge with effect from 11 July 2018 after considering that this project meets the 3 prescribed criteria for project to be declared as “Stressed Project”.

8.2. The DPT has proposed the rationalized storage charge with reference to the upfront tariff Order dated 17 August 2010. The DPT has not updated the revised storage charge with the applicable indexation factors to arrive at the current revised storage charge after the applicable indexation. The applicable indexation factor under the upfront tariff guidelines of 2008 is cumulative indexation of 25.67% upto the year 2018-19 for the base year 1 January 2010, and thereafter annual indexation factor of 2.07% and 2.56% for the years 2018-19 and 2019-20 respectively. A comparative position of the storage charge approved by this Authority in the upfront tariff Order dated 17 August 2010, storage charge notified in the name of the AKBTPPL in the Order dated 2 January 2015, the revised rationalized storage proposed by the DPT and the revised rationalized storage approved by this Authority on ad hoc basis for import / export cargo after the applicable indexation factor are given below:

- (i). **Storage Charges prescribed in the tariff Order No.TAMP/42/2009-KPT dated 17 August 2010:**  
(Rate in ₹ Per MT per day)

Commodity	Rate for 1 <sup>st</sup> day to 10 <sup>th</sup> day	Rate for 11 <sup>th</sup> day to 20 <sup>th</sup> day	Rate for 21 <sup>st</sup> onwards
All types of cargo	2.07	4.14	6.21

- (ii). **Indexed Storage Charges notified in the name of AKBTPPL in the tariff Order No.TAMP/59/2014-KPT dated 02 January 2015**

(Rate in ₹ per MT per day)

Commodity	Rate for 1 <sup>st</sup> day to 10 <sup>th</sup> day	Rate for 11 <sup>th</sup> day to 20 <sup>th</sup> day	Rate for 21 <sup>st</sup> onwards
All types of cargo	2.54	5.07	7.61

- (iii). **Revised rationalized Storage charge proposed by the DPT with reference to the original tariff Order dated 17 August 2010**

(Rate in ₹ per MT per day)

Commodity	Rate for 1 <sup>st</sup> day to 10 <sup>th</sup> day	Rate for 11 <sup>th</sup> day to 20 <sup>th</sup> day	Rate for 21 <sup>st</sup> onwards
All types of cargo	₹0.29	₹0.57	₹0.86

- (iv). **Revised rationalized Storage charge proposed by the DPT indexed with applicable indexation factor to arrive at the rates as on the date of the approval by the Authority (25.67 % + 2.07% + 2.56%)**

(Rate in ₹ per MT per day)

Commodity	Rate from 1 <sup>st</sup> day to 10 <sup>th</sup> day	Rate from 11 <sup>th</sup> day to 20 <sup>th</sup> day	Rate from 21 <sup>st</sup> day onwards
All types of cargo	₹0.38	₹0.75	₹1.13

9. As stated earlier, the DPT in its proposal dated 21 December 2019 has proposed the rationalized storage charge. The rate proposed by DPT is with reference to the upfront storage tariff approved in the upfront tariff Order dated 17 August 2010. The DPT has not applied the applicable indexation factor with reference to the rationalised (i.e. reduced) storage charge to arrive at the revised storage charge after the applicable indexation. Subsequent to joint hearing, the DPT vide its email dated 13 March 2020 has furnished the proposed rationalised indexed storage charges beyond free period after applying applicable indexation factor as given below:

Revised proposed tariff w.e.f.	Rate from 1 <sup>st</sup> day to 10 <sup>th</sup> Day	Rate from 11 <sup>th</sup> Day to 20 <sup>th</sup> Day	Rate from 21 <sup>st</sup> Day onwards
11.07.2018 to 31.07.2018	0.36	0.73	1.09
01.08.2018 to 31.03.2019	0.37	0.74	1.12
01.04.2019	0.38	0.76	1.14

10. The proceedings relating to joint hearing held in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the arguments made by the parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website <http://tariffauthority.gov.in>.

11. With reference to the totality of the information collected during the processing of the case, the following position emerges:

(i). The proposal mooted by the Deendayal Port Trust (DPT) seeks approval of this Authority for rationalisation of indexed upfront tariff for storage charges for Dry Bulk Terminal off Tekra near Tuna approved by this Authority vide Order No.TAMP/59/2014-KPT dated 02 January 2015 while notifying the SOR for Dry Bulk Terminal developed off Tekra near Tuna outside Kandla creek by the BOT operator M/s. Adani Kandla Bulk Terminal Pvt. Ltd. (AKBTPL) on Build, Operate and Transfer (BOT) basis under Public Private Partnership (PPP) model with DPT which is governed by the upfront tariff guidelines of 2008, in pursuance of Ministry of Shipping (MOS) letter No.PD-13/1/2018-PPP Cell dated 11 July 2018 issued to all Major Ports to deal with Stressed PPP projects.

(ii). As already brought out in the earlier paragraphs, this Authority had vide Order No.TAMP/42/2009-KPT dated 17 August 2010 fixed upfront tariff for the Dry Bulk Terminal developed off Tekra near Tuna outside Kandla creek on BOT basis under PPP model with DPT under the upfront tariff guidelines of 2008.

The DPT has awarded the project to AKBTPL. In compliance of the provisions of Guidelines, the SOR was notified in the name of AKBTPL vide Order No.TAMP/59/2014-KPT dated 2 January 2015 after indexing the notified upfront tariff approved by this Authority in the tariff Order of 17 August 2010.

(iii). The current proposal of DPT is taken up for processing because it is filed in pursuance of the MOS letter dated 11 July 2018 to the Major Port Trusts as regards the stressed PPP project.

(iv). The MOS in its letter dated 11 July 2018 has prescribed the three criteria for classification of PPP project as Stressed Projects by Major Port Trusts which has been brought out in para 7.2 above and hence not reiterated for the sake of brevity. The Board of Trustees of the DPT has declared the project handled by the AKBTPL as Stressed Project. The port has furnished the following as regards the three criteria prescribed in the MOS letter which has been considered by the Board of Trustees of the DPT for declaring the project of AKBTPL as Stressed Project:

(a). As regards the first parameter, the capacity utilisation for the preceding two years furnished by the DPT being below 70% as exhibited by DPT is tabulated below:

Year	Cargo Handled (MMT)
2016-17	4.45
2017-18	4.20

[The port has not furnished capacity utilisation in terms of percentage. The Port has, however, stated that this project was awarded to AKBTPL at DPT on BOT basis with a capacity of 14.112 MTPA as per the upfront tariff approved by this Authority. The capacity utilization at traffic reported to have been handled by the AKBTPL in the

preceding two years as tabulated above works out to 31.53% in the year 2016-17 and 29.76% in the year 2017-18 i.e. capacity utilization is below 70%.]

- (b). As regards the other two parameters, the port has furnished the Certificate of Chartered Accountant from the Auditors of AKBTPL certifying the cash losses and net worth of AKBTPL for the preceding two financial years as tabulated below:

(₹ in lakhs)

Year	Cash Loss (Refer note 2 below)	Net Worth	Net Loss
2014-15	Not furnished	1,420.30	-580.42
2015-16	Not furnished	-4,022.20	-15,442.50
2016-17	-3,374.32	-13,137.74	-9,130.13
2017-18	-5,566.75	-24,531.42	-11,393.68

From above, it is seen that there has been cash losses of ₹33.74 crores in the financial year 2016-17 and ₹55.67 crores in the year 2017-18. Further, the net worth of the AKBTPL is reported to be negative to the tune of (-)₹131.38 crores in financial year 2016-17 which has increased to negative net worth of (-)₹245.31 crores in financial year 2017-18 which is more than 50% erosion prescribed as one of the criteria for declaring the project as stressed project.

- (v). (a). The Board of Trustees of DPT has approved the rationalised storage charge with effect from 11 July 2018 after considering that this project meets the 3 prescribed criteria for project to be declared as “Stressed Project”. The underutilisation of capacity below 70% is supported by the DPT letter and the cash loss for preceding two years 2016-17 and 2018-19 and erosion of net worth of at least 50% is supported by the Certificate from practicing Chartered Accountant furnished by AKBTPL and considered by the Board of Trustees of the DPT. The same is relied upon.

The DPT has for removal of the stress of the Project, as per the MOS directives, proposed to rationalize the tariff for storage for this project. Based on the actual evacuation of cargo from this project, during the years 2015-16, 2016-17 and 2017-18 and by keeping the revenue requirement for storage for the project same as per the originally approved tariff for the project at ₹11.68 crores, the proposed tariff for storage, beyond free period, is worked out by the DPT. The DPT has also furnished the revenue estimation at the proposed rationalised storage charge to show that at the proposed rationalised storage charge, the revenue matches with the ARR estimated from storage in the original tariff Order No.TAMP/42/2009-KPT dated 17 August 2010 relating to fixation of upfront tariff for dry bulk terminal. The detailed calculations for the proposed tariff for storage is furnished by the DPT which is brought out in the earlier para of this order and hence not reiterated here for the sake of brevity.

The proposal filed by the DPT is based on the approval of the Board of Trustees of the DPT; it fulfills the three criteria prescribed in the MOS letter dated 11 July 2018 on the Stressed Project and the proposal of the DPT is to help to remove one project of the DPT from stress and to revive it. Therefore, this Authority is inclined to approve the indexed rationalised storage charge proposed by the DPT. There is slight mismatch in the indexed rationalised storage arrived by the DPT in the second decimal point vis-à-vis the indexed rationalised storage arrived by us applying the applicable indexation factor. The indexed rationalised storage proposed by the DPT is corrected to that extent considering the applicable indexation factor announced by this Authority.

- (vi). The DPT has in its proposal dated 21 December 2019 sought approval of the rationalised storage charge with retrospective effect from 11 July 2018 i.e. from the date the MOS issued the letter dated 11 July 2018 as regards stressed PPP Projects. The proposal of the DPT is based on the approval accorded by the Board of Trustees of DPT for retrospective effect from 11 July 2018.

Ordinarily this Authority does not approve to rates with retrospective effect. It is relevant here to state that the said MOS letter dated 11 July 2018 does not contain any provision for retrospective

effect of rationalisation in storage charges of Stressed PPP project. When sought clarification in this regard with a request to DPT to propose the rationalised rate with prospective effect as per the ordinary practice followed by this Authority, the DPT has stated that its proposal towards rationalization of storage tariff may not be construed as retrospective for the purpose of its effectiveness and be approved w.e.f. 11 July 2018, the date on which the MOS has communicated the Guidelines/ directives for Stressed Project.

As regards retrospective effect of the proposed rationalised storage charge sought by the DPT, it is relevant here to draw reference to the proceedings of the joint hearing wherein the AKBTPPL has stated that it has given an undertaking dated 3 December 2019 to DPT wherein it has undertaken to pay the revenue share @ 25.09% as per the Concession Agreement on storage charge accrued till 10 July 2018 (i.e. 1 day prior to the MOS letter dated 11 July 2018) calculated as per approved upfront tariff along with interest thereon and from 11 July 2018 onwards the AKBTPPL have undertaken to pay revenue share to the DPT on storage charge based on rationalised storage charge to be approved by this Authority along with interest thereon or on ARR considered to arrive at the storage charge in the TAMP Order of the 2010, whichever is higher. The DPT has also confirmed this position and categorically stated that this arrangement is a win-win situation for the port and the AKBTPPL. The DPT has further stated that AKBTPPL is expected to reach 6.5 MTPA in the current financial year 2019-20 and have promised to handle 10 MTPA traffic in the next year 2020-21 and this proposal will help to revive the this stressed project and has also been highlighted this aspect as one of the achievements of the DPT to the Ministry of Shipping.

In view of the above position and also recognizing that the Board of Trustees of the DPT have vide resolution dated 6 December 2019 approved the rationalised storage charge with retrospective effect from 11 July 2018, this Authority approves the proposal of the DPT for retrospective effect from 11 July 2018 i.e. from the date of MOS letter till 19 February 2020 i.e. the adhoc approval granted by this Authority to the amended rationalised storage charge proposed by the DPT.

- (vii). The DPT had in the original proposal proposed the rate arrived at the level of 2010 without indexation and had proposed a note for annual indexation. However, subsequently, DPT has proposed the indexed rationalised storage charge which is to be prescribed subject to minor correction in the second decimals. Hence the note proposed by the DPT for indexation of the rate is not found relevant.

It is relevant here to state that the indexed amended storage charge proposed by the DPT captures the indexation factor applicable for the year 2019-20. The BOT operators governed under the 2008 guidelines are entitled for annual indexation @ 60% of the WPI announced by this Authority. The AKBTPPL is governed under the upfront tariff guidelines of 2008 and hence is entitled for annual indexation for the year 2020-21 announced by this Authority on the rationalised amended storage charge approved in the Order dated 24 July 2019. The indexation factor announced by this Authority for the year 2020-21 under the upfront tariff under 2008 guidelines @ 60% of the WPI is 1.13%. Therefore, the indexed rate applying 1.13% indexation factor shall be applicable from 1 April 2020 till 19 February 2021 and accordingly is included in the schedule of rationalised storage charge.

- (viii). Since the current proposal of the DPT is for a limited period of one year and recognizing that the storage charge and the free period prescribed in the SOR notified in the name of the AKBTPPL is for the entire project period of 30 years subject to annual escalation, the existing note nos.(i) to (iii) relating to storage charge as per the schedule 4 in the SOR is prescribed herein separately for ease of application instead of tinkering with the existing Scale of Rates of the AKBTPPL approved by this Authority in the Order No.TAMP/59/2014-KPT dated 2 January 2015.
- (ix). The DPT has proposed a note that the proposed Rationalized Tariff for storage will be reviewed after one year from date of Notification i.e., the proposed tariff will be effective for initial period of one year or approval of revised tariff, if any, post review whichever is later. In this regard, it is relevant to state that as per Para 6 of the MOS letter dated 11 July 2018 Concessional Authority is to review the situation periodically for optimum utilization of the facility created. In the case of the other stressed projects at the VPT, the VPT had sought approval of the rationalised storage charge for a period of one year and to review thereafter and the approval was granted by this Authority for the period of one year from the date of in-principle approval accorded for the two stressed PPP projects of the VPT. In the instant case, since the rationalised storage charge was approved by this Authority on adhoc basis from 20 February 2020, validity of the amended storage schedule is approved by this Authority for the period of one year from that date when adhoc approval was granted till 19 February 2021. Further, for the reasons stated earlier, the proposal of the DPT for

retrospective effect for the period 11 July 2018 i.e. from the date of the MOS letter till 19 February 2020 when the adhoc approval was granted by this Authority is approved. Thus, the note proposed by the DPT is modified to state that it is prescribed from 11 July 2018 and shall be valid till 19 February 2021.

12.1. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, the storage charge applicable as per existing schedule 4 in the Order No.TAMP/59/2014-KPT dated 02 January 2015 approved by this Authority notifying the SOR in the name of the AKBTPPL is replaced with the following schedule until its validity period prescribed till 19 February 2021.

Sl. No.	Particulars	(in ₹ per tonne per day or part thereof) Amended indexed Storage Charge for the period <u>11.07.2018 till 19.02.2021</u>		
		11.07.2018 to 31.03.2019	For the year 2019-20	For the period 01.04.2020 to 19.02.2021
1.	Storage Charges from 1st day to 10th day	0.37	0.38	0.39
2.	Storage Charges from 11 <sup>th</sup> day to 20th day	0.73	0.75	0.76
3.	Storage Charges from 21st day onwards	1.10	1.13	1.14

**Note for Section 4**

- (i). Five free days for import cargo and fifteen free days for export cargo shall be allowed. For the purpose of calculation of free period, Customs notified holidays and Terminal's non- working days shall be excluded.
- (ii). Storage charges shall be payable for all days including Terminal's non- working days and Customs notified holidays for stay of cargo beyond the prescribed free days.
- (iii). Storage charge on cargo shall not accrue for the period when the terminal operator is not in a position to deliver / ship the cargo when requested by the user due to reasons attributable to the terminal operator.
- (iv). The above storage schedule is approved for the period from 11 July 2018 and shall be valid till 19 February 2021.

12.2. The AKBTPPL is also directed to furnish the quarterly physical performance including the cargo-wise volume handled through DPT within 15 days on the end of each quarter and annual performance, both physical and financial, within 2 months at the end of the financial year to this Authority.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./63/2020-21]